



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1-

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2005/माघ 4, 1926

No. 23]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2005/MAGHA 4, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

मध्यावधि समीक्षा

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ, जार्जिया और सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन ए पामिटेट के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।

सं. 15/12/2004-डीजीएडी.— यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियम भी कहा गया है) के अंतर्गत दिनांक 23 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 65/1/2001-डीजीएडी के द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, जॉर्जिया और सिंगापुर (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन ए पामिटेट (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था। संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 7 मार्च, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 40/2003 सीमाशुल्क के द्वारा लगाया गया था।

2. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा के लिए यूरोपीय संघ के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों में से एक निर्यातक अर्थात् मै० बी ए एस एफ, ए जी, जर्मनी और यूरोपीय आयोग से एक आवेदन प्राप्त हुए था। उपर्युक्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक सूचना के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना कि निर्यातक द्वारा प्राधिकारी की जानकारी में लायी गयी परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उपर्युक्त होगा। तदनुसार, प्राधिकारी ने उपर्युक्त संबद्ध देशों पर लागू शुल्क के संबंध में पाटनरोधी

करार के अनुच्छेद 11.2 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत के बारे में दिनांक 30 अगस्त, 2004 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क को लगातार लागू रखना अपेक्षित है और क्या शुल्क को समाप्त करने अथवा उसे परिवर्तित करने अथवा इन दोनों स्थितियों में क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

3. इस कार्यवाही में मूल जांच 24.1.2002 को शुरू की गयी थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 30.4.2002 की अधिसूचना सं० 65/1/2001-डीजीएडी के तहत जारी की गयी थी और दिनांक 13.8.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 80/2002 सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर अंतिम शुल्क लगाया गया था तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.1.2003 की अधिसूचना सं० 65/1/2001-डीजीएडी के जरिए अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे और दिनांक 7.3.2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 40/2003-सीमाशुल्क द्वारा अंतिम शुल्क लगाया गया था।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

(i) समीक्षा की शुरुआत करने के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजी:

जर्मनी

बी ए एस एफ एक्टीन्ज सेल साफ्ट
कार्ल बोस-स्ट्रेज, 38
67056, लुड विग्सचैफेन,
जर्मनी

फ्रांस

रोन पाउलेस सा(एवेंटिस)
कोर्बोई सेडेक्स
फ्रांस

सिंगापुर

बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया प्रा० लि०
7, टेमसेक बोलवार्ड,
35-01 सेंटेंक टावर वन,
सिंगापुर-038987
दूरभाष सं० (65)3370330 फैक्स: (65)3340330

एवेंटिस एनीमल न्यूट्रीशन एशिया पैसिफिक प्रा० लि०

1, लोयांग वे 4, सिंगापुर-507028

दूरभाष: (65)5431121 फ़ैक्स: (65)5453708

दूरभाष: 85228278068

फ़ैक्स: सं० 85228276023

- (ii) नियमावली के अनुसार संबंधित सूचना हेतु भारत में घरेलू उद्योग को भी नोटिस भेजे गए थे ।
- (iii) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गयी थी और यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें ।
- (iv) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गयीं ।
- (v) यह जांच 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 की अवधि के लिए की गयी थी । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2000-01 से 2003-04 की अवधि शामिल होगी ।
- (vi) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था ।
- (vii) समीक्षा हेतु आवेदक को छोड़कर संबद्ध देशों के किसी अन्य निर्यातक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ।
- (viii) बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर और भारत में जार्जिया के अवैतनिक वाणिज्य दूत ने अपने संक्षिप्त अनुरोध प्रस्तुत किए थे ।
- (ix) संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक एवं मूल जांच में मूल याचिकाकर्ता मै० निकोलस पिरामल इंडिया लि०, मुम्बई ने समीक्षा का विरोध करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया था ।
- (x) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त सभी विचारों और अनुरोधों पर संभव सीमा तक विचार किया है ।
- (xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पक्षों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।
- (xii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने के लिए सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर इष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध

वस्तु को बनाने और बेचने की लागत की गणना करने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की संभव सीमा तक सत्यापन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xiii) यूरोपीय संघ के आवेदक निर्यातक ने सत्यापन हेतु अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे।

(xiv) प्राधिकारी ने 30.07.2004 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन हितबद्ध पार्टियों को मौखिक रूप से सुनने के लिए किया जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, यूरोपीय संघ के संबद्ध वस्तुओं के आवेदक निर्यातकों ने भाग लिया था। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था।

(xv) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों एवं निर्धारण के आधार का खुलासा 5 जनवरी, 2005 के पत्रों द्वारा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष सामान्य प्रकटन विवरणों और शामिल पार्टियों के समक्ष गोपनीय प्रकटन विवरणों के रूप में किया गया था। हालांकि घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरणों पर अपनी टिप्पणियाँ दायर की हैं तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो यूरोपीय आयोग ने और न ही आवेदक निर्यातक ने प्रकटन विवरण का कोई उत्तर दिया है। तथापि, घरेलू उद्योग से प्राप्त प्रकटन विवरणों पर इन जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है।

(xvi) **** यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माने जाने का द्योतक है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद विटामिन ए पामिटेट है जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और आई टी सी एच एस वर्गीकरण की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में शीर्ष सं0 293621.00 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। परिवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा जांच होने के कारण मूल जांच में सम्मिलित उत्पाद ही इस जांच में शामिल है। किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के मुद्दे पर कोई तर्क नहीं दिया गया है और इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित तथा संबद्ध देशों से विनिर्मित एवं निर्यातित उत्पाद हर प्रकार से समान हैं।

घ. समीक्षा की शुरुआत और दिए गए तर्क

घ.1 समीक्षा हेतु आवेदक अर्थात् मै0 बी ए एस एफ ए जी, जर्मनी के विचार

6. समीक्षा हेतु आवेदन यूरोपीय आयोग के माध्यम से मै0 बी ए एस एफ ए जी, जर्मनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवर्तित परिस्थितियों में जांच की शुरुआत हेतु दिनांक 21 जून, 2004 के मूल आवेदन एवं दिनांक 27 अगस्त, के पूरक आवेदन में आवेदनकर्ता निर्यातक ने निम्नलिखित आधार देते हुए समीक्षा हेतु अनुरोध किया है:

पाटन:

- मार्च, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 40/2003- सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाने के बाद बी ए एस एफ ने मै० *** को विटामिन ए पामिटेड 1.7 एम आई यू/ग्रा. के *** किग्रा० का केवल *** परेषण किया है। उपर्युक्त सौदा भारत के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण का प्रतिनिधिक है। उपर्युक्त सौदे के आधार पर भारत के लिए ई सी निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति किग्रा० निर्धारित की गयी है।
- ई यू और ई सी के लिए बिक्री कीमत के आधार पर विटामिन ए पामिटेड की घरेलू कीमत *** अमरीकी डालर बनती है।
- उपरोक्त निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के आधार पर ई यू से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन नकारात्मक है।

ii. कीमत कटौती

- ई यू से निर्यात कीमत और भारत में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर कोई कीमत कटौती नहीं हुई है।

iii. कम कीमत पर बिक्री

- विटामिन ए पामिटेड डी पी सी ओ, 1995 के अंतर्गत शामिल है। जनवरी, 2003 में इस मामले में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के लगाने के बाद से विटामिन ए के लिए डी पी सी ओ कीमतों को दो बार संशोधित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा निर्धारित विटामिन ए पामिटेड की डी पी सी ओ कीमत मूल जांच अवधि अर्थात् 01.01.2001 से 30.09.2001 की तुलना में 23.34% तक गिर गई है।
- मूल जांच अवधि (01.01.2001 से 30.09.2001) के दौरान : 1 एम आई यू/ ग्रा. आधार पर 3178 रु./कि.ग्रा., जो 1.7 एम आई यू/ग्रा. आधार पर 5402.60 रु./कि.ग्रा. बनती है। प्रचलित विनिमय दर से यह कीमत 115.00 अम. डालर/कि.ग्रा. बनती है।
- 07.12.2003 से प्रभावी : 1 एम आई यू/ग्रा. आधार पर 2452 रु./कि.ग्रा., जो 1.7 एम आई यू/ग्रा. आधार पर 4168.40 रु./कि.ग्रा. बनती है।
- 03.03.2004 से प्रभावी : 1 एम आई यू/ग्रा. आधार पर 2436 रु./कि.ग्रा., जो 1.7 एम आई यू/ग्रा. आधार पर 4141.20 रु./कि.ग्रा. बनती है। प्रचलित विनिमय दर के साथ यह कीमत 86.38 अमरीकी डालर/कि.ग्रा. बनती है।
- तथापि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयात कीमत अथवा संदर्भ कीमत अपरिवर्तनीय रही है। इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम आयात कीमत फिलहाल डीपीसीओ द्वारा निर्धारित कीमत से पर्याप्त रूप से अधिक है, जो गैर-क्षतिकारक स्तर पर है। अतः ई यू से आयातों द्वारा कोई कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

iv. कारणात्मक संबंध

- यह तथ्य कि जर्मन निर्यातक के लिए उत्पादन की लागत *** अम. डालर है और डी पी सी ओ द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्री कीमत 86.36 अम. डालर (4141.20 रु.) है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय घरेलू उद्योग के लिए समानता का बिंदु जर्मन निर्यातकों से बहुत अधिक ऊँचे स्तर पर है। यह संकेत करता है कि कथित पाटन आयातों के अतिरिक्त कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, हो रही है।

7. तथापि समीक्षा जांच के आरम्भ होने के पश्चात् आवेदक पाटन, यदि कोई हो, की मात्रा और सीमा के निर्धारण के लिए अपेक्षित पूर्ण प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करने में असफल हो गया है। इसके बाद यूरोपीय आयोग, जिनके जरिए समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, ने वह प्रथम आधार वापस ले लिया था जिस पर समीक्षा के लिए अनुरोध किया गया था अर्थात् यूरोपीय संघ से कोई पाटन नहीं। उन्होंने यह तर्क दिया है कि समीक्षा के लिए अनुरोध केवल क्षति दावे के आधार पर किया जा सकता है और समीक्षा के लिए ई यू के अनुरोध के कानूनी अनुपालन के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना पाटन के पहलू को हटाया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि समीक्षा अनुरोध में पाटन हिस्से के अभाव में क्षति के बारे में जांच परिणाम अभी दिए जाने बाकी हैं और एक नकारात्मक जांच परिणाम के परिणामस्वरूप उपायों की समाप्ति हो जाएगी चूंकि यह डब्ल्यू टी ओ नियमों के अंतर्गत अनिवार्य है।

8. संक्षेप में ई सी के तर्क इस मूल आधार-वाक्य पर आधारित हैं कि पाटन और क्षति निर्धारण एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं और पाटन की मौजूदगी में भी शुल्क को रद्द करने की आवश्यकता होगी यदि यह पाया जाता है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। अतः उन्होंने तर्क दिया है कि पाटन संबंधी सूचना उपलब्ध कराने की आवेदक की बाध्यता क्षति संबंधी जांच के लिए नगण्य है, जिसे मुख्यतः वास्तविक क्षति पर केन्द्रित होना चाहिए, जो उनके विचार में बाजार गतिशीलता में परिवर्तन, ई सी निर्यातकों द्वारा वसूली जा रही कीमत का ध्यान किए बिना मौजूद नहीं है।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार :

9. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में समीक्षा की शुरुआत का विरोध किया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया है कि भारतीय विधान के अनुसार कोई भी समीक्षा पाटन और क्षति दोनों पर लागू होगी; अतः भारतीय विधान में या तो पाटन अथवा क्षति की आंशिक समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

10. घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया है कि जांच आरम्भ होने से पूर्व समीक्षा के लिए आवेदक द्वारा कुछ सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिसे आवेदक ने उपलब्ध नहीं कराया है और उपरोक्त के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मध्यावधि समीक्षा आरम्भ नहीं करनी चाहिए थी।

11. घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया है कि समीक्षा के आवेदनकर्ता निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से समीक्षा के आरम्भ होने के बाद भी सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि चूंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत संबंधी सूचना आवेदनकर्ता के पास उपलब्ध है, यह उनका प्रथम उत्तरदायित्व बनता है कि वे यह सूचना निर्धारित प्रपत्र और ढंग से उपलब्ध कराएं और समीक्षा के लिए आवेदनकर्ता होने के कारण अपने दावे के

समर्थन में साक्ष्य का दायित्व आवेदक का है। इस संबंध में उन्होंने न्यायाधिकरण और न्यायालयों में निर्णय लिए गए मुद्दे पर विधि-शास्त्र का उल्लेख किया है।

12. घरेलू उद्योग के विचार में उत्पादन की लागत और सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना सिर्फ निर्यातक के क्षेत्र के भीतर आती है। इस तथ्य को दबाकर निर्यातक समीक्षा की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है इसलिए, निर्यातक को पहले कानूनों और प्राकृतिक न्याय के द्वारा उनको दिए गए दायित्व को पूरा करना अपेक्षित है।

13. संक्षेप में घरेलू उद्योग के तर्क ये हैं कि समीक्षा आवेदक निर्यातक द्वारा पाटन न करने के दावों को साबित करने वाले पूरे साक्ष्यों और घरेलू उद्योग को कोई क्षति न होने के अभाव में और पाटन न किए जाने के दावे को साबित करने के प्रमाण का भार आवेदक द्वारा क्षति का साक्ष्य प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग का बचाव करने से पहले सर्वप्रथम उसी पर रहेगा, समीक्षा शुरू नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कानून के अनुसार पाटन और क्षति जांच अपृथक्करणीय हैं और दोनों की जांच साथ-साथ की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या शुल्क को हटाने अथवा उतार-चढ़ाव की अवस्था में पाटन अथवा क्षति पुनः उत्पन्न होने की संभावना है।

14. प्रकटन विवरण के बाद अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने आवेदक द्वारा सबूत के भार और समीक्षा के शुरूआत के लिए अपेक्षित सकारात्मक सूचना के स्तर के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि आवेदक ने अपुष्ट साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा शुरू करने में प्राधिकारी को भ्रमित किया है और उनके द्वारा शुरू की गई जांच में चुनिंदा भागीदारी से इस जांच की समूची प्रक्रिया में गंभीर विसंगति उत्पन्न हो गई है।

15. जहाँ तक समीक्षा की शुरूआत का संबंध है, ऊपर यह नोट किया जा चुका है कि प्राधिकारी का दायित्व उसके समक्ष प्रस्तुत सकारात्मक सूचना पर गौर करना है जिससे समीक्षा की जरूरत के यथोचित आधार का पता चलता हो। जांच की कार्यवाही के दौरान प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सूचना के आधार पर 'संतुष्टि' के कारक की जांच करनी होती है। प्राधिकारी ने समीक्षा का अनुरोध करने के बाद निर्यातक के असहयोग को नोट किया है और जहाँ तक पाटन का संबंध है, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं।

घ. 3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार :

16. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समीक्षा की शुरूआत के बारे में प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध अथवा तर्क नहीं दिया है। तथापि सिंगापुर और जॉर्जिया ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

बी ए एस एफ सिंगापुर

17. बी ए एस एफ सिंगापुर ने सूचित किया है कि बी ए एस एफ साउथ ईस्ट एशिया पी टी ई लि० किसी भी प्रकार के विनिर्माण कार्यकलाप में शामिल नहीं है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि उन्होंने बी ए

एस एफ, जर्मनी के लिए केवल समन्वय और बीजक संबंधी सेवाएं की हैं और विचाराधीन उत्पाद बी ए एस एफ जर्मनी से भारत को प्रत्यक्ष रूप से भेजी गई हैं।

जॉर्जिया

18. भारत में जॉर्जिया के माननीय वाणिज्य दूतावास ने प्राधिकारी से जॉर्जिया के सम्बद्ध वस्तु के निर्यातकों के नाम व पते उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तथापि चूंकि प्राधिकारी के पास इनके ब्योरे उपलब्ध नहीं थे, ये उपलब्ध नहीं कराए जा सके। वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि ने सार्वजनिक सुनवाई में भी अपनी स्थिति दोहराई।

19. घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने सिंगापुर और जॉर्जिया के अनुरोधों का विरोध नहीं किया है।

घ. 4. प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने यूरोपीय आयोग के इन तर्कों को ध्यान में रखा है कि परिवर्तित परिस्थिति समीक्षा में पाटन और क्षति निर्धारण दो अलग और भिन्न जांच हैं और इनका अलग-अलग निर्धारण किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कोई पाटन और क्षति नहीं आधार पर अनुरोध करने पर यूरोपीय निर्यातकों और ई सी के लिए यह आवश्यक था कि वे दोनों गणनाओं के लिए अपने दावों को प्रमाणित करें। ई सी ने भी दावा भी किया है कि पाटन का जारी रहना अथवा जांच अवधि के दौरान पाटन न होने की क्षति जांच पर कोई बाध्यता नहीं है, जो एकमात्र ऐसी जांच है जो उद्योग की मौजूदा स्थिति के आधार पर जांची जा रही है।

21. पाटनरोधी नियमों के नियम 23 के साथ पठित धारा 9क (5) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाए रखने को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और यदि वे अपने द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट होते हैं कि ऐसे शुल्क लगाना जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो वे इसको समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं।

22. करार के अनुच्छेद 11.2 में यह व्यवस्था है कि प्राधिकारी स्वयं अपनी ओर से आवश्यकतानुसार शुल्क के निरंतर लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उचित समयावधि व्यतीत हो चुकी हो, यह कार्य किसी हितबद्ध पक्षकार जिसने समीक्षा की आवश्यकता को साबित करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की हो, के अनुरोध पर किया जाएगा। हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारियों से यह अनुरोध करने का अधिकार होगा कि यह जांच की जाए कि क्या पाटन का निराकरण करने के लिए शुल्क को लगातार लागू रखना आवश्यक है, क्या शुल्क को हटा दिए जाने अथवा परिवर्तित कर दिए जाने अथवा दोनों से क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यदि इस पैराग्राफ के अंतर्गत की गई समीक्षा के फलस्वरूप प्राधिकारी यह निर्धारण करें कि पाटनरोधी शुल्क की आगे आवश्यकता नहीं है तो इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

23. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्यातक द्वारा पाटन न करने और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होने के दावे के दावों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्यों की अनुपस्थिति में इस समीक्षा को शुरू नहीं किया जाना चाहिए और आवेदक द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति का कोई साक्ष्य देने का समर्थन करने से पहले कोई पाटन न किये जाने के दावे को साबित करने का प्रमाण देने का दायित्व निभाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कानून के अनुसार समीक्षा में पाटन एवं क्षति की जाँच अलग-अलग नहीं है और यह निर्धारित करने के लिए दोनों की जाँच एक साथ की जानी चाहिए कि क्या शुल्क को हटाने या इसमें परिवर्तन करने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

24. समीक्षा के लिए आवेदकों ने तर्क दिया है कि पाटन एवं क्षति के निर्धारक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और पाटन की मौजूदगी में भी शुल्क को हटाये जाने की आवश्यकता है, यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। अतः पाटन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का आवेदक का दायित्व निराधार है, जिसे प्राथमिक रूप से क्षति पर केन्द्रित होना चाहिए।

25. प्राधिकारी ने इन तर्कों की जाँच की है और उनका यह विचार है कि नियम 23 में दी गई 'संतुष्टि' की शर्त का अभिप्राय उचित ढंग से जाँच करने के बाद शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता के संबंध में प्राधिकारी की संतुष्टि से है और न कि समीक्षा की शुरुआत से। समीक्षा की शुरुआत करने के लिए प्राधिकारी के पास ऐसी सकारात्मक सूचना का होना आवश्यक है जिस पर वह यह निर्णय लेने के लिए भरोसा कर सकते हों कि क्या शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की जाँच के लिए समीक्षा आवश्यक है। इस मामले में आवेदक ने प्राधिकारी के समक्ष सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की थी और प्रस्तुत की गई इस सकारात्मक सूचना के आधार पर समीक्षा की शुरुआत की गई थी। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए दावों और उनके विरुद्ध दावों को साबित करने के लिए साक्ष्यों की प्रस्तुति जाँच का विषय है और जाँच की प्रक्रिया के दौरान इन्हें समीक्षा हेतु अनुरोध करने वाले पक्षकार समेत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। तथापि समीक्षा का परिणाम समीक्षा के लिए विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणता पर निर्भर होगा। अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि इस समीक्षा की शुरुआत प्राधिकारी के पास उपलब्ध सकारात्मक सूचना जिससे यह साबित हुआ कि लागू शुल्क की समीक्षा करने की आवश्यकता थी के आधार पर उचित ढंग से की गई है।

26. तथापि पाटन और क्षति की जाँच अलग-अलग करने के मुद्दे पर और कोई पाटन नहीं किए जाने के दावों को सही साबित करने के प्रमाण के दायित्व के संबंध में करार के अनुच्छेद 11.2, 11.3 और अनुच्छेद 3.4 के संदर्भ में आवेदक के तर्कों की जाँच की गई है। अनुच्छेद 11.3 में यह व्यवस्था है कि यदि इस समीक्षा में पाटन एवं क्षति दोनों शामिल हों, तो इसके परिणामस्वरूप निश्चयात्मक शुल्क को आगे पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके निहितार्थ में आंशिक समीक्षा की व्यवस्था है जिसमें पाटन या क्षति में से कोई एक या, व्यापक समीक्षा जिसमें दोनों शामिल हों। तथापि प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल क्षति को कवर करने वाली समीक्षा पाटन के स्तर एवं मात्रा की पूर्णतः अनदेखी कर सकती है।

27. करार के अनुच्छेद -3 में यह प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मापदंडों की जाँच पाटित आयातों के संदर्भ में की जाएगी। अनुच्छेद 3.1 में यह व्यवस्था है कि:

'गैट 1994 के अनुच्छेद VI के प्रयोजनार्थ क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्यों पर आधारित होगा और इसमें इन दोनों (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों की घरेलू बाजार में

कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वैकल्पिक जाँच शामिल होगी।

इसके अलावा अनुच्छेद 3.4 में यह व्यवस्था है कि "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री, लाभों, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत पर प्रभाव डालने वाले कारकों; पाटन मार्जिन की मात्रा का मूल्यांकन शामिल होगा।"

28. अतः करार के उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है कि पाटनरोधी जाँच के संदर्भ में घरेलू उद्योग की स्थिति की किसी जाँच में मात्रा और मार्जिन के अनुसार पाटन के निहित प्रभावों और पाटन की मात्रा पर विचार करना होगा।

29. अनुच्छेद 11.2 में पुनः यह प्रतीत होता है कि यदि अनुच्छेद 11.2 के उक्त प्रावधानों को दो भागों में बाँटा जाए, जैसीकि ईसी द्वारा व्याख्या की गई है, तो भी इस प्रावधान के दूसरे वाक्य में यह व्यवस्था है कि पक्षकार समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं और प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि 'क्या यदि शुल्क को हटाया या इसमें परिवर्तन किया जाए तो क्षति के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।'

इस प्रावधान में प्राधिकारी द्वारा वर्तमान क्षति यदि कोई हो और क्या यदि शुल्क को हटाया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति हो सकती है की जाँच की अपेक्षा की गई है। इस प्रावधान के दूसरे भाग पर विचार करते समय पाटन की मात्रा यह निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा कि यदि उसे उपलब्ध शुल्क संरक्षण के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है तो भी क्या यदि शुल्क को हटाया गया तो घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

30. करार के उपर्युक्त सभी प्रावधानों में यह निहित है कि यदि यह निर्णय करने में कि क्या शुल्क को जारी रखना आवश्यक है, घरेलू उद्योग की स्थिति की जाँच करने के लिए आंशिक समीक्षा आवश्यक है, और इसके निहितार्थों द्वारा पाटन की जाँच, जांच का अभिन्न अंग बन जाती है और पाटन की वर्तमान स्थिति और घरेलू उद्योग की वर्तमान दशा के अलावा समीक्षा को भविष्य में पुनरावृत्ति की संभावना की मौजूदगी पर विचार करना चाहिए। अतः ईसी की यह दलील कि परिवर्तित परिस्थितियों के अंतर्गत समीक्षा एक बिल्कुल अलग प्रकार की जाँच है और इसे इस बात पर विचार किये बिना किया जाना कि पाटन हो रहा है अथवा नहीं, उचित अथवा व्यवहार्य प्रतीत नहीं होती है।

31. ईसी ने यह दलील भी दी है कि समीक्षा के अनुरोध से पाटन के पहलू को आसानी से हटाया जा सकता है और इससे ईसी के समीक्षा संबंधी अनुरोध के विधायी अनुपालन पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक सूचना के आधार पर यदि एक बार समीक्षा की शुरुआत की जाती है तो वादी पक्षकारों का यह दायित्व है कि वे पाटन एवं क्षति समेत विभिन्न पहलुओं पर अपने-अपने दावे और विरुद्ध दावे प्रस्तुत करें। चूंकि समीक्षा के लिए आवेदकों ने कोई पाटन नहीं किए जाने के दावे को वापस लेने का निर्णय लिया है और घरेलू उद्योग ने ईयू के उत्पादकों, जिनका प्रतिनिधित्व ईसी द्वारा नहीं किया गया है, द्वारा पाटन के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, इसलिए प्राधिकारी के पास एडीए के अनुच्छेद 6.8 के अनुसार सर्वोत्तम तथ्यों के अंतर्गत प्रतिकूल अनुमान लगाने और जहाँ तक पाटन का संबंध है प्रतिवादी के दावे को

स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इन प्रतिकूल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मानते हुए कि पाटन जारी है प्राधिकारी इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, की जाँच करते हैं।

32 प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो निर्यातक ने और न ही यूरोपीय आयोग ने सामान्य प्रकटन विवरणों में घोषित प्राधिकारी के उपर्युक्त विचारों पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत की है और न ही उसका विरोध किया है।

ड. पाटन का निर्धारण

ड. पाटन का निर्धारण: सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

ड.1 यूरोपीय संघ

सामान्य मूल्य

33. मै0 बीएसएफ एजी, जर्मनी ने अपनी घरेलू बिक्री कीमत और भारत को निर्यात कीमत के संबंध में सारांश आँकड़ों के साथ समीक्षा की शुरुआत के बाद एक संक्षिप्त उत्तर प्रस्तुत किया है और यह दावा किया है कि '****' ईयूआर/किग्रा. की उनकी कारखाना द्वार पर घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में भारत को कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत '****' ईयू आर/किग्रा. है। तथापि उन्होंने अपनी घरेलू तथा निर्यात बिक्रियों के सौदेवार आंकड़े और दावा किए गए विभिन्न तत्वों संबंधी आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं। आवेदक ने बिना किसी आँकड़ों की प्रतिलिपि और अन्य पद्धतियों के केवल अपनी लागत संरचना का सारांश भी प्रस्तुत किया है। इन सारांश आँकड़ों के आधार पर समीक्षा के आवेदक ने यह दावा किया है कि उनकी उत्पादन लागत '****' ईयूआर/किग्रा. है। यद्यपि आवेदक ने आँकड़ों के सार प्रस्तुत किये हैं और प्राधिकारी से यदि अपेक्षित हो तो सत्यापन करने का आग्रह किया है तथापि वे उत्पादन घरेलू तथा निर्यात बिक्री कीमत के किसी पहलू पर, इसके लिए अनुरोध करने और प्राधिकारी द्वारा आँकड़ों के सत्यापन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने का अनुरोध करने के बावजूद ब्यौरेवार आँकड़े प्रस्तुत करने में विफल रहे थे। आवेदक निर्यातक ने ब्यौरेवार सूचना और सत्यापन हेतु उनकी सहमति के अनुरोध संबंधी पत्राचार का कोई उत्तर नहीं दिया।

34. अपने अनुरोध में यूरोपीय आयोग ने यह तर्क दिया है कि कोई पाटन नहीं किये जाने के उनके दावे को वापस लिया हुआ माना जाना चाहिए और इस बात पर विचार किये बिना की पाटन हो रहा है या नहीं प्राधिकारी को केवल क्षति संबंधी पहलू की जाँच करने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती खण्ड में यह दर्शाया गया है कि शुल्क को हटाये जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या इसकी संभावना की आंशिक समीक्षा में भी पाटन की मात्रा का आकलन निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है।

35. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मै0 बीएसएफ कानून द्वारा यथापेक्षित ढंग से इन प्रक्रियाओं में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में सीमित अनुरोध प्रस्तुत किये हैं और आसानी से अपने सामान्य मूल्य से संबंधित किसी सूचना को उपलब्ध न कराने का विकल्प चुना है। यह स्थापित कानून एवं न्याय शास्त्र के विरुद्ध है। अतः किसी सूचना के अभाव में, घरेलू उद्योग, द्वारा प्राप्त की गई सूचना को चल रहे पाटन की मात्रा के आकलन के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का आधार माना जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने ईयू में प्रचलित घरेलू कीमतों के साक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया। यद्यपि वह जाँच अवधि के लिए कीमतें प्राप्त नहीं कर पाया है तथापि उसे एक बीजक प्राप्त हुआ है। उन्होंने ईयू के निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ इस बीजक में दी गई कीमत के आधार पर ईयू में कारखाना द्वार पर कीमत की गणना की है।

36. करार के अनुच्छेद 6.8 में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले जिसमें कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा प्रभावी ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्रारंभिक एवं अंतिम निर्धारण, चाहे सकारात्मक हों अथवा नकारात्मक, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जा सकते हैं। करार के अनुबंध II में आगे यह प्रावधान है कि ऐसे निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भी किए जा सकते हैं।

37. इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार करार के अनुच्छेद 6.8 के अनुरूपे ई यू निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य स्वीकृत किए हैं जो ***** रु. प्रति कि.ग्रा. परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

38. डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। डी जी सी आई एण्ड एस ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के निम्नानुसार आयात की सूचना दी है।

	मात्रा कि.ग्रा. में विटामिन ए पामिट्रेट 1.7 एमआईयू/ग्राम ई क्यू		
देश	2003-04		
	मात्रा	सी आई एफ मूल्य	दर रु./कि.ग्रा.
कुल ई यू	300.59	1071549	3564.84
सिंगापुर	88.24	299033	3389.04
अन्य	2746.29	9124310	3322.41
कुल	3046.88	10195859	3346.33

इन आंकड़ों के आधार पर ई यू निर्यातकों के लिए निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत का परिकलन घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सी आई एफ कीमत में विभिन्न समायोजनों की अनुमति देने के बाद किया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ***** रु. प्रति किलोग्राम निर्धारित की गयी है।

पाटन मार्जिन :

39. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित सामान्य मूल्य की कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत से तुलना की गई है। ई यू निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार परिकलित किया गया है :

पाटन मार्जिन का परिकलन

	सामान्य मूल्य रु./कि.ग्रा.	निर्यात कीमत रु./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन रु./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %
ई यू निर्यातक	*****	*****	*****	16.52%

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक अथवा यूरोपीय आयोग ने स्पर्युक्तानुसार तथा सामान्य प्रकटन विवरणों के जरिए सूचित पाटन मार्जिन की पद्धति अथवा उसके निर्धारण पर न तो कोई टिप्पणी की है और न ही उसका विरोध किया है।

ड.2. सिंगापुर और जार्जिया

41. यह नोट किया गया है कि जार्जिया से संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं किया गया है तथा इस देश में संबद्ध वस्तु के किसी विनिर्माता अथवा निर्यातक के बारे में कोई सूचना किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए पाटन अथवा इस देश से पाटन की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है।

42. जहां तक सिंगापुर का सम्बन्ध है, बी ए एस एफ दक्षिण पूर्व एशिया प्रा0 लि0 ने यह उल्लेख किया है कि वह किसी प्रकार के विनिर्माण कार्यकलाप नहीं कर रहा है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे बी ए एस एफ जर्मनी के लिए केवल संयोजन तथा बीजक संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा विद्याराधीन उत्पाद बी ए एस एफ कंपनी द्वारा सीधे भारत को भेजा जाता है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि सिंगापुर से निर्यात पुननिर्यात अथवा जर्मनी मूल की वस्तुओं का केवल यानांतरण कहे जा सकते हैं। तदनुसार सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य करार के अनुच्छेद 2.5 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। अतः सिंगापुर में सामान्य मूल्य **** रु. प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के आधार पर निवल कारखाना द्वारा निर्यात कीमत *** रु. प्रति किलो परिकलित की गई है।

पाटन मार्जिन (सिंगापुर)

पाटन मार्जिन का परिकलन

	सामान्य रु./कि.ग्रा.	मूल्य रु./कि.ग्रा.	निर्यात कीमत रु./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन रु./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %
सिंगापुर निर्यातक	*****	*****	*****	*****	23.69 %

43. संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन काफी पाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पार्टी ने प्रकटन विवरणों के जरिए सूचित इस निर्धारण का विरोध नहीं किया है।

च. क्षति निर्धारण

च.1. क्षति का संचयी आकलन

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जार्जिया से वह अवधि जिसके लिए क्षति की जांच की गई है, में पाटित आयात नहीं हुए हैं। यद्यपि सिंगापुर से आयात हुए हैं जो जर्मनी के मूल के प्रतीत होते हैं। ई यू तथा सिंगापुर से आयात को पाटित आयात माना गया है क्योंकि निर्धारित पाटन मार्जिन घनात्मक है। प्रचलित प्रतिस्पर्धा की स्थिति के मद्देनजर तथा ई यू एवं सिंगापुर से आयातों के समान उद्गम होने के तथ्य के मद्देनजर, इन देशों/क्षेत्रों से सभी आयातों को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ संचित किया गया है।

च.2. क्षति का जारी रहना

च.2.1. आवेदकों के विचार

45. समीक्षा करने के लिए आवेदकों ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन में सुधार किया है

तथा उन्हें कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग जिसका प्रतिनिधित्व एकमात्र उत्पादक मै0 निकोलस पीरामल इंडिया लि0 द्वारा किया जाता है ने अपने निष्पादन में उत्पादन तथा क्षमता उपयोग, भण्डार सूची स्तर तथा निर्यात निष्पादन के रूप में सुधार किया है तथा '****' रु./कि.ग्रा. ('****' अमरीकी डालर/कि.ग्रा.) की औसत कीमत पर अप्रैल से अगस्त, 2004 के दौरान '****' कि.ग्रा. का उनका निर्यात यह इंगित करता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। उन्होंने आगे दलील दी है कि जनवरी, 2003 में विटामिन ए पामिट्रेट पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद विटामिन ए पामिट्रेट की डी पी सी ओ कीमत में राष्ट्रीय भेषज कीमत प्राधिकरण (एन पी पी ए) द्वारा दो बार अधोगामी संशोधन किए गए हैं। 03.03.2004 से प्रभावी डी पी सी ओ कीमत विटामिन ए पामिट्रेट 1.7 के लिए 5402.6 रु./कि.ग्रा. (115 अम. डा./कि.ग्रा.) से घटाकर 4141.20 रु./कि.ग्रा. (86.38 अम. डा./कि.ग्रा.) कर दी गई है। इसी अवधि के दौरान ई यू से कीमतें मूल जांच अवधि (1.1.01 से 20.09.01) की तुलना में वर्तमान जांच अवधि (01.04.03 से 31.03.04) के दौरान बढ़ी। उसके परिणामस्वरूप न्यूनतम आयात कीमत डी पी सी ओ के तहत निर्धारित कीमत की तुलना में वर्तमान में पर्याप्त रूप से उच्चतर है (पहले से ही क्षतिरहित स्तर पर)। इसलिए बी ए एस एफ ए जी से निर्यातों पर घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की कोई सम्भावना नहीं है। आगे उनकी यह दलील है कि निकोलस पीरामल इंडिया लि0 की लाभप्रदता 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान बढ़ी है। इसलिए यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि बी ए एस एफ से आयातों के कारण क्षति हुई है तथा इसलिए कारणात्मक सम्बन्ध अनुपस्थित है।

च.2.2. घरेलू उद्योग के विचार

46. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि इस मामले में जिसके विरुद्ध कीमत निर्धारण की समीक्षा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को घरेलू उद्योग ने याचिका प्रस्तुत की थी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत में डी पी सी ओ (ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर) कीमत द्वारा किए गए कीमत संशोधन पर बहुत अधिक विश्वास किया गया है। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए कार्यों को डी पी सी ओ से पृथक् प्रयोजन तथा प्रयोज्य नियमों के कारण पृथक् निकाय हैं।

47. इस मामले में अंतिम जांच परिणाम को उद्धृत करते हुए घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उक्त जांच परिणाम में प्राधिकारी ने एन पी पी ए द्वारा डी पी सी ओ के तहत निर्धारित की गई कीमतों के पृथक्करण को मान्यता दी थी तथा प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित क्षतिरहित कीमत यह इंगित करती है कि डी पी सी ओ द्वारा दो पृथक् तथा सुस्पष्ट कीमतें तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अन्य कीमतें निर्धारित की गई थीं।

48. उन्होंने आगे यह दलील दी है कि उपर्युक्त स्थिति सही है क्योंकि डी पी सी ओ द्वारा कीमतों को उर्ध्वगामी या अधोगामी संशोधित करने की स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए हर बार इसकी जांच परिणामों की समीक्षा करना अव्यावहारिक होगा।

49. आवेदक निर्यातक के इस तर्क का उल्लेख करते हुए कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत से क्षति का संकेत नहीं मिलता है क्योंकि कीमतें डी पी सी ओ द्वारा निर्धारित कीमतों से कम हैं, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इस बात से कि निर्यातक द्वारा पाटन किया जा रहा है अथवा नहीं ओर ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है अथवा नहीं, घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत का कोई संबंध नहीं है।

50. यह भी तर्क दिया गया है कि क्षति की समीक्षा का मानदंड कई न्यायिक निर्णयों में स्वाभाविक रूप से स्थापित क्षति की जाँच के लिए अपेक्षित मानदंड से परे है। अपीलीय प्राधिकरण ने यह माना है कि क्षति के निर्धारण पर विचार करते समय वास्तविक क्षति के खतरे के मानदंड पर अनिवार्य रूप से विचार किया जाए। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि ई यू की निर्यात कीमतों और निर्यातक के पास तथा ई यू में उपलब्ध क्षमता को देखते हुए इस समीक्षा के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के भीतर वास्तविक क्षति के अतिरिक्त आर्थिक क्षति का वास्तविक एवं आसन्न खतरा विद्यमान है।

51. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि मूल याचिका में वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के भीतर जाँच अवधि के दौरान ई यू की औसत निर्यात कीमत 3164.29 रु० प्रति कि.ग्रा. थी। इस मध्यावधि समीक्षा की जाँच अवधि के दौरान शुल्क लगाए जाने के बावजूद निर्यात कीमत में मात्र मामूली वृद्धि हुई है। अतः स्पष्ट रूप से घरेलू भारतीय बाजार में कीमत प्रभाव को महसूस किया जा रहा है जिससे निर्यात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मूल जाँच अवधि से सीमाशुल्क में कमी के पश्चात् घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव और भी अधिक है। अतः पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि होगी।

च.2.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

52. नियम 11 तथा नियमावली के अनुबंध II में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित की वस्तुपरक जाँच किया जाना अपेक्षित है :-

- (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों का प्रभाव दोनों और
- (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का अनुवर्ती प्रभाव।

चूँकि संबद्ध देश से आयातों को पाटित आयात माना गया है अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर इन पाटित आयातों के मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव की जाँच और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को ऐसे पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है, क्षति मानदंडों के विश्लेषण का प्रस्ताव करते हैं।

(क) मात्रात्मक प्रभाव

(क) आयातों की मात्रा तथा आयात कीमतें :

53. क्षति विश्लेषण अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षति जाँच अवधि के दौरान यूरोप तथा सिंगापुर सहित विभिन्न स्रोतों से आयात हुए हैं। तथापि, जॉर्जिया से किसी आयात की रिपोर्ट नहीं है। यह भी देखा गया है कि विटामिन- ए पामिटेट के आयातों को अलग-अलग स्ट्रेथ अर्थात् 1.0 और 1.7 एम आई यू/ग्रा. के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है। चूँकि इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत दोनों स्ट्रेथ को शामिल किया गया है अतः सभी आयातों को विटामिन- ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/ग्रा. के समतुल्य में परिवर्तित किया गया है। तदनुसार, डी जी सी आई एंड एस द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आँकड़े निम्नानुसार हैं :-

आयात विवरण		विटामिन- ए पामिटेट 1.7 एम आई यू/ग्रा. समतुल्य	
		मूल्य सी आई एफ रु. में	मात्रा कि.ग्रा. में
वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04

देश	मात्रा	मूल्य	दर	मात्रा	मूल्य	दर	मात्रा	मूल्य	दर
कुल ई यू	7271	22295955	3066.42	1549	4981655	3216.05	300 59	1071549	3564.84
सिंगापुर	350	1104224	3154.93	0	0		88.24	299033	3389.04
अन्य	2042	5027265	2461.93	1925	6190387	3215.79	2746.29	9124310	3322.41
कुल	9663	28427444	2941.89	3474	11172042	3215.90	3135.12	10494892	3347.53

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

54. उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में 2001-02 के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने के बाद आयातों की कुल मात्रा में गिरावट आई है। तथापि, जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है पिछले कुछ वर्षों में कुल आयातों में संबद्ध देशों के हिस्से में काफी गिरावट आई है। यद्यपि वर्ष 2001-02 से संबद्ध देशों से कुल आयातों में अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित हुई है और संबद्ध देशों से आयात में गिरावट बहुत अधिक है। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि संबद्ध देशों पर शुल्क भारत में पहुँच कीमत पर आधारित संदर्भ कीमत के रूप में है, उक्त अवधि के दौरान कीमतों में बहुत कम वृद्धि हुई है।

55. प्रकटन विवरण के बाद अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए आयात संबंधी आंकड़ों का इस आधार पर खंडन किया है कि गौण स्रोत अर्थात् आई बी आई एस के जरिए उपलब्ध आंकड़ों से डी जी सी आई एंड एस द्वारा सूचित आयात से अधिक आयात का पता चलता है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में केवल विटामिन ए-पाथिटेट शामिल है। अतः पाटन मार्जिन और क्षति निर्धारण हेतु आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करते समय अन्य स्वरूपों में आयातित विटामिन-ए तथा उसी शीर्ष के अन्तर्गत सूचित अन्य असंबद्ध आयातों को सही विश्लेषण हेतु उक्त विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण की पद्धति को भी प्रकटन विवरण में ही स्पष्ट किया गया है और इसलिए इस संबंध में घरेलू उद्योग की आपत्ति वैध नहीं है।

(ख) घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

56. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग और इन मानदंडों पर पाटित आयातों का प्रभाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में उसके निष्पादन की भी जांच की गई है।

57. घरेलू उद्योग ने संकेत दिया है कि उस तरल संयंत्र के लिए जहाँ संबद्ध वस्तु का विनिर्माण होता है, उसकी कुल स्थापित क्षमता एकल पारी आधार पर 110 मी. टन प्रति वर्ष है। तथापि, यह नोट किया गया है कि यह स्थापित क्षमता विचाराधीन उत्पाद के प्रति समर्पित नहीं है और इस संयंत्र में कंपनी लगभग 35 अलग-अलग उत्पादों का विनिर्माण करती है। माँग के आधार पर विशिष्ट उत्पाद के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन होता रहता है।

58. अतः उत्पादक की क्षमता का आकलन तीन पारी में प्रचालन जो संयंत्र के लिए वास्तव में उपलब्ध है और विचाराधीन उत्पाद सहित विभिन्न उत्पादों का संयंत्र में कुल उत्पादन के आधार पर किया गया है। तदनुसार, क्षमता एवं क्षमता उपयोग का परिकलन निम्नानुसार किया गया है :-

वर्ष	स्थापित क्षमता (कि.ग्रा.)	उत्पादन (सभी उत्पादक (कि.ग्रा.)	क्षमता उपयोग (%)
2000-01	*****	*****	46.60
2001-02	*****	*****	33.40
2002-03	*****	*****	48.50
2003-04	*****	*****	55.40

59. उपर्युक्त जाँच से यह प्रदर्शित होता है कि जाँच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग जाँच अवधि सहित पिछले चार वर्षों में उच्चतम है। अतः क्षमता अथवा क्षमता उपयोग से घरेलू उद्योग के निष्पादन में अवनति का संकेत नहीं मिलता है।

(ग) माँग एवं बाजार हिस्सा

60. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में की गई आपूर्तियाँ, आबद्ध उपभोग, अन्य तीसरे देशों से आयात के साथ-साथ संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में किए गए आयातों की संयुक्त मात्रा के आधार पर कुल माँग का अनुमान लगाया गया है।

मात्रा कि.ग्रा. में

घरेलू उद्योग का उत्पादन				
	*****	*****	*****	*****
विटामिन ए 1.0	*****	*****	*****	*****
विटामिन ए 1.7	*****	*****	*****	*****
कुल	*****	*****	*****	*****
कुल उत्पादन 1.7 एम आई यू/ग्रा. समतुल्य	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	100	55.31	76.55	97.70
कुल आयात 1.7 एम आई यू/ग्रा. समतुल्य	5100.00	9663.00	3474.00	3135.12
संबद्ध देशों के आयात	4550.00	7621.00	1549.00	388.82
% (संबद्ध देश)	89%	79%	45%	12%
घरेलू बिक्री	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	100	25.14	67.63	67.40
आबद्ध उपभोग	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	100	291.5	165.3	344.4
माँग	*****	*****	*****	*****
सूचीबद्ध	100	78.15	78.42	96.68
बाजार हिस्सा				
घरेलू उद्योग	85.53%	64.93%	87.43%	90.80%
संबद्ध देश	12.91%	27.66%	5.60%	1.14%
अन्य	1.56%	7.41%	6.96%	8.06%

61. जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की माँग में वर्ष 2000-01 में 35 मी. टन से वर्ष 2003-04 में 34 मी. टन तक मामूली गिरावट आई है। उसी समय कुल आयातों में भी सापेक्ष रूप से और साथ ही बाजार हिस्से के रूप में अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित हुई है। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 85% से बढ़कर 91% हो गया है। जहाँ तक पाटित आयातों के हिस्से का संबंध है इस मामले में जिन देशों पर शुल्क लगाया गया है, उनका हिस्सा कुल बाजार हिस्से का 1% है जो वर्ष 2000-01 में लगभग 13% से कम है। कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में और कुल माँग में अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित होती है। अतः आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि शुल्क लगाए जाने के पश्चात् बाजार हिस्से और उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और पाटित आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है। तथापि, वर्तमान परिदृश्य पहले से ही लागू शुल्क की पृष्ठभूमि में है।

तथापि, मौजूदा परिदृश्य पहले ही लागू शुल्क की पृष्ठभूमि में है।

(ख) कीमत प्रभाव:

(क) घरेलू उद्योग की बिक्री वसूली

62. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वर्ष 2000-2001 में ***** रु./किग्रा. से कम होकर जांच अवधि के दौरान ***** रु./किग्रा. हो गई है जिसमें वर्ष 2000-2001 के स्तरों से 18.29% की कमी प्रदर्शित होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन लागत में भी अत्यधिक कमी आयी है। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमतें इसके द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार निम्नानुसार हैं :-

सूचीबद्ध आंकड़े

वर्ष	प्रति मी.टन बनाने और बेचने की लागत (रु.)	प्रति मी. टन बिक्री (रु.)	प्रति मी. टन लाभ/(हानि) (रु.)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	102.33	93.11	(188.32)
2002-2003	85.15	97.22	466
2003-2004	79.56	81.71	147.40

63. यह देखा जाता है कि उत्पादन लागत वर्ष 2000-2001 में लगभग ***** रु./किग्रा. से अत्यधिक कम होकर वर्ष 2003-2004 में ***** रु./किग्रा. हो गई है जो कि लगभग ***** रु./किग्रा. की कमी है। बिक्री कीमतों में समान गिरावट भी लगभग 8888 रु./किग्रा. की है। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री कीमत में यह गिरावट अधिक है जबकि लागत में मामूली कमी हुई है। इस उत्पाद के प्रति कि.ग्रा. लाभ में शुल्क लागू करने के पश्चात सुधार प्रदर्शित होने के पश्चात वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के बीच तीव्र गिरावट प्रदर्शित हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट डीपीसीओ के कीमत संशोधन से उत्पन्न हुई मालूम होती है।

64. यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी उत्पादन के विभिन्न कारकों और निवेश पर तर्क संगत आय को ध्यान में रख कर जांच अवधि के लिए क्षति रहित कीमत को ***** रु./किग्रा. के रूप में निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों के साथ तुलना करने पर उत्पाद के प्रति किग्रा. लाभ मार्जिन में सुधार प्रदर्शित होगा क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत से अधिक है।

ख. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

65. कीमत कटौती के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की ईयू और सिंगापुर से संचयी आयातों के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध वस्तु (सीआईएफ कीमत + मूल सीमाशुल्क) के पहुँच मूल्य के साथ तुलना की गई थी। सिंगापुर और ईयू से आयातों की भारित औसत सीआईएफ कीमत के आधार पर पहुँच मूल्य ***** रु./किग्रा. के रूप में परिकलित किया गया है। निम्नलिखित तालिका में ईयू से कीमत कटौती की मात्रा को दर्शाया गया है:-

वर्ष	घरेलू बिक्री कीमत	आयात कीमत (पहुँच मूल्य)	कम कीमत पर बिक्री
2003-2004	*****	*****	नकारात्मक

66. इसलिए संबद्ध देशों के आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर कोई कटौतीकारी प्रभाव नहीं पड़ा है। चूँकि आयातों का यथा उम्र निर्धारित पहुँच मूल्य भी घरेलू उद्योग के लिए

प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत से अधिक है, इसलिए आयातों का घरेलू कीमतों पर कोई कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव भी नहीं पड़ा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एनपीपीए ने डीपीसीओ विनियमन के तहत विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिकतम कीमत को 1.0 एमआईयू/जी आधार पर 2436 रु./किग्रा. के स्तर तक संशोधित कर दिया है जो दिनांक 03.03.2004 से 1.7 एमआईयू/जी आधार पर 4141.20 रु./किग्रा. बनती है। उपर्युक्त अधिकतम कीमत के आधार पर आयातों के पहुंच मूल्य का भी घरेलू कीमतों पर नकारात्मक कीमत कटौती और कीमत संबंधी प्रभाव पड़ा है।

(ग) क्षति के अन्य मापदंड:

67. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति के प्रमुख संकेतकों जैसे आयातों की मात्रा और मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा घरेलू उद्योग की बिक्रियों के साथ-साथ पूर्ववर्ती भाग में विभिन्न खण्डों के बाजार हिस्से के साथ मांग पद्धति की जांच करने के पश्चात अन्य आर्थिक मापदंडों जो घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शा सकते थे, का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:-

(क) लाभप्रदता

68. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का विश्लेषण कम्पनी के रिकार्ड से किया गया है:-

वर्ष	लाभ/(हानि) लाख रूपए
2000-2001	100
2001-2002	(49.85)
2002-2003	321.95
2003-2004	114.73

69. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का लाभ पिछले वर्ष 2002-2003 में ***** रूपए मिलियन से घट कर जांच अवधि के दौरान ***** रूपए मिलियन हो गया है। वार्षिक आधार पर प्रतिशत के रूप में लाभ पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान *****% कम हुआ। तथापि लाभ में गिरावट जैसा कि ऊपर उल्लिखित है इस तथ्य के बावजूद है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का बहुत कम आयात हुआ है और पाटित आयातों का कोई कीमत कटौती अथवा कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव नहीं पड़ा है। पाटित आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और डीपीसीओ कीमत से काफी अधिक है। इसलिए, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट में पाटित आयातों का योगदान मालूम नहीं होता है।

(ख) रोजगार

70. जहाँ तक रोजगार और मजदूरी का संबंध है घरेलू उद्योग की क्षति के संकेतक के रूप में रोजगार के स्तर में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आयी है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी द्वारा मजदूरी में कमी के रूप में लागत में कमी करने वाले महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं।

(ग) उत्पादता

71. इस अवधि के दौरान उत्पादन में कमी के कारण प्रति कर्मचारी उत्पादन के लिहाज से उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट आयी है।

सूचीबद्ध

वर्ष	कर्मचारियों की सं०	उत्पादन (किग्रा.)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (किग्रा.)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	101	52.95	52.19
2002-2003	101	71.69	70.66
2003-2004 (जांच अवधि)	100	91.64	91.65

(घ) माल सूचियां

सूचीबद्ध

वर्ष	प्रारंभिक स्टॉक मी. टन	अंतिम स्टॉक मी. टन
2000-2001	100	100
2001-2002	50	0
2002-2003	0	139
2003-2004	695	21

72. कम्पनी की मालसूची संबंधी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित हुआ है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के स्टॉक्स इसी अवधि के दौरान आरंभिक स्टॉक की तुलना में कम होकर ***** मी० टन हो गया।

(ड.) निवेश और निवेश पर आय

73. जांच अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा क्षमता में कोई वृद्धि अथवा कोई नया निवेश नहीं किया गया है।

74. निवेश पर आय शुल्क लगाने के पश्चात हुई भारी वृद्धि के बाद अत्यधिक कम होकर लगभग *****% हो गई है। तथापि जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, लाभ में कमी उन पाटित आयातों के कारण नहीं है जो क्षति रहित कीमत और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने के लिए प्रस्तावित एनआईपी से अधिक पहुंच लागत पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

सूचीबद्ध

वर्ष	(%)
2000-2001	100
2001-2002	(227)
2002-2003	692
2003-2004	211

(च) पाटन की मात्रा

75. संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा जिस सीमा तक घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति पहुँचा सकती है, से यह प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि के लिए संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन जब भी पाटनरोधी शुल्क लागू था, पर्याप्त था।

(छ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

76. पाटित आयातों जो घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, से भिन्न कारकों का विश्लेषण करने के लिए लागत ढाँचे में परिवर्तन, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापन कीमतों की जांच की गयी है। इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है और निकोलस पिरामल भारत में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है। अतः घरेलू प्रतिस्पर्धा कीमतों को प्रभावित नहीं करती है। केवल अन्य कारक जो घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकता था वह है डी पी सी ओ कीमतें।

(ज) अन्य ज्ञात कारक**(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा एवं कीमत**

77. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भिन्न केवल अमरीका, चीन और स्विटजरलैंड से आयात हुए हैं। इन स्रोतों से हुए कुल आयात संबद्ध देशों से हुए आयातों की तुलना में काफी अधिक हैं। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि अपाटित स्रोतों से हुए आयात कुल आयातों का 87 प्रतिशत है और इन स्रोतों से भारत औसत आयात कीमत संबद्ध देशों से हुए पाटित आयात कीमतों से कम है। अतः संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा एवं मूल्य दोनों के अनुसार घरेलू उद्योग पर पर्याप्त प्रभाव प्रतीत नहीं होता है।

(ii) मांग में कमी और/अथवा खपत के ढाँचे में परिवर्तन

मात्रा किग्रा. में

	2000-01	2001-02	2002-03	सूचीबद्ध 2003-04
मांग	100	78.15	78.42	96.68

78. विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक घटने के पश्चात जांच अवधि में पर्याप्त वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी आधार वर्ष के स्तर से कम रह गया है। मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है जबकि संबद्ध देशों के हिस्से में पर्याप्त गिरावट आई है। साथ ही, अन्य स्रोतों से आयातों के हिस्से में मांग के 1.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अतः मांग में कमी होना एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है।

(iii) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनके व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार

79. संबद्ध माल मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है। मैसर्स निकोलस पिरामल देश में संबद्ध माल का एकमात्र उत्पादक है। तथापि, औषधि कीमत नियंत्रण घरेलू उत्पादकों के उत्पाद की बिक्री कीमत को सीमित करता है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से हुए आयातों की भारतीय बाजार में काफी अच्छी पकड़ है जिसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(iv) प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात निष्पादन

80. प्रौद्योगिकी अथवा प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के रूप में किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा नहीं उठाया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग निर्यात निष्पादन को आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारण के रूप में उठाया गया है क्योंकि घरेलू उत्पादक संबद्ध माल का निर्यात अन्य देशों को काफी कम कीमत पर करते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि निर्यात कीमत का निर्णय इस उत्पाद के लिए नए बाजार स्थापित करने हेतु उनकी बाजार प्रवेश नीति पर आधारित होता है क्योंकि वैश्विक बाजार में वे लघु प्रतिस्पर्धी हैं। प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और उनकी राय यह है कि घरेलू उद्योग ने बाजार प्रवेश अभियान के रूप में जांच अवधि के दौरान अत्यंत लघु मात्रा में निर्यात किया है और उससे कंपनी की लाभप्रदता पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ता है।

(v) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

81. श्रम उत्पादन और दैनिक उत्पादन के अनुसार घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पर्याप्त गिरावट प्रदर्शित हुई है। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में, उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

च.5 पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना

82. चूंकि प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित कर दिया है कि संबद्ध माल संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में निरंतर प्रवेश कर रहा है इसलिए इसके पुनरावृत्ति के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तथापि, संबद्ध देशों में उत्पाद के सामान्य मूल्य के आधार पर विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करने के लिए निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटित कीमतों पर निर्यातों का बाजार में प्रवेश होना जारी रहेगा। लेकिन उस कीमत स्तर को देखते हुए जिस पर उत्पाद सभी स्रोतों से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है। इसकी संभावना नहीं है कि निर्यात कीमतों में तत्काल और गिरावट आ सकती है।

83. अतः यह जांच करना आवश्यक है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है अथवा उसमें घट-बढ़ की जाती है तो क्या घरेलू उद्योग को इन पाटित आयातों के कारण पुनः क्षति होने की संभावना है। यह बात पहले ही सिद्ध हो चुकी है कि बिना पाटनरोधी शुल्क के संबद्ध देशों से आयातों का उताराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नुकसान रहित कीमत से काफी अधिक है। अतः संदर्भ कीमत के अनुसार निर्धारित शुल्क को समाप्त करने से कीमत स्तर पर वास्तविक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

84. तथापि, वास्तविक क्षति की जांच करने के अलावा प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने अथवा क्षति के खतरे की संभावना की भी जांच की है।

85. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वास्तविक क्षति के खतरे की जांच नियमावली के अनुबंध II (vii) के अनुसार की जानी चाहिए जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

" वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा और न कि केवल आरोप, कल्पना अथवा परोक्ष संभावना के आधार पर। परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी स्थिति का स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति आसन्नवर्ती होनी चाहिए जिसमें पाटन से क्षति पहुंचेगी। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में आकलन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:-

(क) भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना प्रदर्शित होती हों;

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्यातक की पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता अथवा उसमें तत्काल पर्याप्त वृद्धि जिसे भारतीय बाजार को अत्यधिक संवर्धित पाटित निर्यातों की संभावना प्रदर्शित होती हो

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों में अत्यधिक गिरावट या कमी आएगी और जिनसे आगे और आयात हेतु मांग बढ़ने की संभावना होगी; तथा

(घ) जांच की जा रही वस्तु का स्टॉक। "

86. यद्यपि किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में उपर्युक्त प्रावधान जांच की समीक्षा में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच के लिए उचित मानदण्ड प्रदान नहीं करता है तथापि, प्राधिकारी ने इस बारे में इस विषय पर निष्कर्ष निकालने के लिए इनमें से कुछेक मानदण्डों की जांच की है।

87. वर्तमान मामले में, संबद्ध माल के आयातों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और मांग में भी अधिक आयात करने के लिए उत्तम वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है

कि उनकी बाजार आसूचना के अनुसार विश्व भर में निर्यातकों की लगभग 5000 मी.टन की क्षमता का अनुमान लगाया जाता है और निर्यातकों के पास पर्याप्त निपटान योग्य क्षमताएं हैं । केवल दो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक हैं जिनके विश्वव्यापी संयंत्र हैं और घरेलू उद्योग की क्षमताएं इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तुलना में काफी कम हैं । अतः इन उत्पादकों के पास भारतीय बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए कीमतों में कटौती करने की भरपूर क्षमता है । तथापि, वर्तमान आयात आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो कीमतों में तुरंत कटौती होगी । जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में पाटित आयातों की उततराई कीमत के कारण पर्याप्त कटौती अथवा कमी प्रदर्शित नहीं होती है जो इन स्तरों से ऊपर है ।

च.6 घरेलू उद्योग की नुकसान रहित कीमत का निर्धारण

88. संबद्ध माल के लिए नुकसान रहित कीमत का परिकलन घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण एवं जांच करने के पश्चात लागत प्रभाग द्वारा किया गया है । प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए भारित औसत क्षति रहित कीमत *** रूपए प्रति किग्रा० निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है । घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण के बाद अपने अनुरोधों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षतिरहित कीमत का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत लेखा परीक्षा के बाद निर्धारित डी पी सी ओ कीमत से भी कम है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत की पद्धति और उसके घटकों को प्रकटन विवरण जारी करने के बाद घरेलू उद्योग को स्पष्ट कर दिया गया है । अतः प्राधिकारी निर्धारित की गई क्षतिरहित कीमत की पुष्टि करते हैं ।

च.7 क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

89. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नुकसान रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यातों के उततराई मूल्य के साथ की गयी है । चूँकि पाटित आयातों के उततराई मूल्य को नुकसान रहित कीमत से अधिक पाया गया है इसलिए जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन को नकारात्मक पाया गया है ।

घ. निष्कर्ष

90. उपर्युक्त सभी मानदण्डों और हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों की जांच करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

क. संबद्ध देशों से पाटन जारी है और इसके जारी रहने की संभावना है।

ख. तथापि, घरेलू उद्योग को इन आयातों के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री वसूलियां और आयात की कीमतें इस प्रकार निर्धारित नुकसान रहित कीमत से अधिक हैं।

ग. यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं तो, घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की संभावना नहीं है।

ज. सिफारिशें

91. संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति न होने का निष्कर्ष निकालने के पश्चात् प्राधिकारी इन देशों के विरुद्ध शुल्क जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं और इसलिए उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुसार इन देशों के विरुद्ध शुल्क समाप्त किए जाने की सिफारिश करते हैं।

झ. आगे की प्रक्रियाएं

92. इस आदेश के विरुद्ध एक अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार दायर की जा सकेगी।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2005

MID TERM REVIEW**FINAL FINDINGS**

Sub : Mid term review of definitive Anti-Dumping duty on imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from the European Union, Georgia and Singapore.

No. 15/12/2004-DGAD.—~~WHEREAS~~ the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after also referred to as the ACT) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after also referred to as Rules), vide Notification Number 65/1/2001-DGAD dated 23rd January 2003, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Vitamin A Palmitate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from the European Union, Georgia and Singapore (hereinafter referred to as subject countries). Definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 40/2003-Customs dated 7th March 2003

2. **AND WHEREAS**, The Designated Authority, received an application from one of the exporters of the subject goods from the European Union i.e. M/s BASF, AG, Germany, and the European Commission for review of the antidumping duties levied on the subject goods, on the grounds of changed circumstances. On the basis of positive information submitted by the above-mentioned applicants the Designated Authority considered that mid-term review of the Anti Dumping Duty in force would be appropriate in view of the changed circumstances brought to the notice to the authority. Accordingly, the Authority issued a public notice dated 30th August 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping mid term review investigation under Section 9A (5) of the Act and Rule 23 of the Antidumping Rules read with Article 11.2 of the Agreement on Antidumping, in respect of the duty in force against the subject countries as above, to determine whether the continued imposition of the duty is required to offset dumping, and whether injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

A. Background of the Case

3. The original investigation in this proceeding was initiated on 24.1.2002. The Preliminary findings was issued by the Designated Authority vide Notification No. 65/1/2001-DGAD dated 30.4.2002 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 80/2002-Cus. dated 13.8.2002 and the final findings was issued by the Designated Authority vide Notification No. 65/1/2001-DGAD dated 23.1.2003 and the final duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 40/2003-Cus. dated 7.3.2003.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, alongwith the initiation notification, to the following known exporters/producers in the subject countries in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information:

Germany

BASF Aktiengesellschaft
CARL-BOSCH-STRASSE, 38
67056, LUDWIGSCHAFEN,
GERMANY.

France

RHONE POULENCE SA (AVENTIS)
Courbevoie Cedex,
France.

Singapore

BASF South East Asia Pvt. Ltd
7, Temasek Boulevard,
35-01, Suntec Tower One,
Singapore – 038987
Tel. No.(65) 3370330 Fax : (65) 3340330

Aventis Animal Nutrition Asia pacific pte. Ltd.
1, Loyang Way 4, Singapore – 507028
Tel : (65) 5431121 Fax (65) 5453708
Tel : 85228278068
Fax No. 85228276023.

- ii) Notices were also sent to the domestic industry in India seeking relevant information in accordance with the Rules;
- iii) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in

accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.

- iv) Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).
- v) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2003 to 31st March 2004. However, injury analysis shall cover the years from 2000-01 to 2003-04.
- vi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;
- vii) No communications were received from any other exporter from the subject countries except the applicant for the review.
- viii) BASF South East Asia, Singapore and the Honorary Consulate of Georgia in India filed their brief submissions
- ix) M/s Nicolas Piramal India Ltd, Mumbai, the domestic producer of the subject goods and the original petitioner in the original investigation submitted its responses opposing the review;
- x) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.
- xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xii) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- xiii) The applicant exporter from the European Union did not submit itself for verification of its data.
- xiv) The Authority held a public hearing on 18th November 2004 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, the applicant exporters of the subject goods from the European Union. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions

received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;

- xv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts considered for these findings and basis of determination were disclosed to known interested parties as general disclosures and confidential disclosures to parties involved vide letters dated 5th January 2005. While the domestic industry has filed its comments to the disclosure statements, the Authority notes that the neither the European Commission nor the applicant exporter has filed any response to the disclosure statement. However, Comments to the disclosures received from the domestic industry has been duly considered in these findings.
- xvi) **** In the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'

5. The product involved in the original investigation and the current review is Vitamin A Palmitate falling under heading No. 293621.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. This being a changed circumstances midterm review investigation, the investigation covers the product covered in the original investigation only. No argument has been extended, by any interested party, on the issue of product under consideration or like article and therefore, the Authority holds that the product being manufactured by the domestic industry and the product being manufactured and exported from the subject countries are alike in all respect.

D. Initiation of the Review and arguments raised

D.1 Views of the applicant for the review i.e., M/s BASF AG, Germany

6. The application for the review has been filed by M/s BASF AG, Germany, through the European Commission. The applicant exporter in its original application dated 21st June 2004, and subsequent supplementary dated 27th August seeking the review cited the following grounds for initiating a changed circumstances review-

Dumping:

- Since the imposition of definitive duty vide Customs Notification No. 40/2003-Customs dated 7 March 2003 BASF AG has shipped only *** consignment of ***** kg of Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/g to M/s *****. The above transaction is representative for determining the export price to India. On the basis of the above transactions the EC export price to India has been determined as US\$***** per Kg
- Based on the sales price for the EU the EC Domestic price of Vitamin A Palmitate is US\$**** per Kg

- On the basis of the above export price and normal value the dumping margin of the subject goods exported from the EU is negative.

ii. Price Undercutting

- On the basis of the export price from the EU and the domestic selling price of the domestic industry in India there is no price undercutting.

iii. Price under selling

- Vitamin A Palmitate is covered under the DPCO, 1995. Since the imposition of the definitive antidumping duty in this case in January 2003, the DPCO prices for Vitamin A have been revised twice. As a result of which the DPCO price of Vitamin A Palmitate fixed by the Government of India has decreased by 23.34 % compared with the original period of investigation i.e. 01.01.2001 to 30.09.2001.
- During the original POI (01.01.2001 to 30.09.2001): Rs.3178/kg on 1 MIU/g basis, which works out at Rs.5402.60/kg on 1.7 MIU/g basis. With the prevailing exchange rate, this price comes to US\$ 115.00/kg
- Effective 07.12.2003: Rs.2452/kg on 1 MIU/g basis, which works out to Rs.4168.40/kg on 1.7 MIU/g basis.
- Effective 03.03.2004: Rs.2436/kg on 1 MIU/g basis, which works out to Rs.4141.20/kg on 1.7 MIU/g basis. With the prevailing exchange rate, this price comes to US\$ 86.38/kg
- However, the minimum import price or the reference price fixed by the Authority has remained unchanged. As a result the minimum import price is currently substantially higher than the price fixed by DPCO, which is at the non-injurious level. Therefore, there is no underselling by imports from the EU and thus no injury to the domestic industry.

iv. Causal Links

- The fact that the cost of production for the German exporter is US\$**** and the maximum selling price fixed by the DPCO is US\$86.36 (RS4141.20) clearly shows that the break even point for the Indian domestic industry lies at a much higher level than the German exporters. This indicates that factors other than alleged dumped imports are causing injury, if any, to the domestic industry.

7. However, after initiation of the review investigation the applicant failed to file complete questionnaire response required for determination of degree and extent of dumping if any. Subsequently, the European Commission, through whom the application for review was filed, withdrew the first ground on which review was requested i.e. no dumping from the European Union. They have argued that the

request for review could stand on the injury claim alone and the dumping aspect could very well be withdrawn without prejudicing in any way the legal compliance of the EU's review request. They have further argued that in the absence of the dumping part in the review request, a finding on injury would still have to be made and a negative finding have to result in the termination of the measures since this is mandatory under WTO rules.

8. In summary the EC's arguments are based on the basic premise that dumping and injury determinations are not interdependent and even in the presence of dumping the duty needs to be revoked if it is found that the domestic industry suffers no material injury. Therefore, they have argued that the obligation of the applicant to provide the information on dumping is immaterial to the injury investigation which has to primarily focus on the material injury which, in their view does not exist due to change in the market dynamics, irrespective of the price charged by the EC exporters.

D.2 Views of the domestic industry:

9. The domestic industry, in its various submissions, has opposed the initiation of the review and has *inter alia* submitted as per Indian law any review shall apply both to dumping and injury; thus, the Indian Law does not have any provision for a partial review of either dumping or injury.

10. The domestic industry has further argued that certain Information are required to be furnished by the applicant for the review prior to initiation, which the applicants did not provide and based on the above, the Hon'ble Designated Authority ought not to have initiated the mid-term review on the basis of the information provided.

11. The domestic industry has further argued that the applicants for the review have failed to provide the information, even after initiation of the review, in the form and manner prescribed. They argue that since the information on Normal value and export prices are available with the applicants it is their primary responsibility to provide the same in the form and manner prescribed and they being the applicants for the review the onus of proof in support of their claim lies with the applicant. In this connection they have cited the jurisprudence on the issue decided in the Tribunal as well as courts of law.

12. In the view of the domestic industry the information concerning cost of production and normal value are solely within the purview of the exporter. By withholding this fact, the exporter is interfering with the process of review and not acting to the best of its ability. Therefore, the exporter first be required to carry the onus placed on them by law and natural justice.

13. In summary the arguments of the domestic industry are that the review should not have been initiated in the absence of complete evidence substantiating the claims of no dumping by the applicant exporter and no injury to the domestic industry and the burden of proof to substantiate the claim of no dumping solely lies with the applicant at the first instance before it shifts to the defending domestic

industry to provide evidence of injury. They have further argued that as per the law, dumping and injury examinations are inseparable in a review and both have to be examined simultaneously to determine whether there is a likelihood of dumping and injury recurring in the event of removal or variation of the duty.

14. In their post disclosure submissions the domestic industry has reiterated its stand on the onus of proof by the applicant and standard of positive information required for initiation of the review. The domestic industry has argued that the applicant has misled the Authority into initiating a review on the basis of unsubstantiated evidences and by selective participation in the investigation initiated by them they have caused serious anomaly in the whole process of this investigation.

15. As far as initiation of the review is concerned it has already been noted above that the obligation on the Authority is to look at the positive information placed before it, which can reasonably indicate the need for a review. The 'satisfaction' factor is to be examined based on the information placed before the Authority during the course of the investigation. The Authority has already taken note of the non-cooperation of the exporter after requesting for a review and as far as dumping is concerned the Authority is free to draw adverse inference based on best facts available.

D.3 Views of the other interested parties:

16. No other interested party has made any submission or argument before the Authority on the initiation of the review. However, Singapore and Georgia have made the following submissions:

BASF Singapore

17. BASF Singapore has conveyed that BASF South East Asia Pte. Ltd is not involved in any type of manufacturing activity. It was also clarified by them that they only carry out coordination and invoicing services for BASF, Germany and the product under consideration is directly shipped to India from BASF Germany.

Georgia

18. Honorary Consulate of Georgia in India requested the Authority to provide the name and address of the exporters of the subject goods from Georgia. However, since details of the same were not available with the Authority the same could not be provided. The representative of the Consulate also reiterated its position in the public hearing.

19. The domestic industry or any other interested parties have not contested the submissions of Singapore and Georgia.

D.4 Examination by the Authority

20. The Authority has taken note of the arguments of the European Commission that the dumping and injury determinations, in a changed circumstances review are two separate and distinct examinations and can be determined in isolation. The domestic industry has argued that having made a request on the grounds of no dumping and injury it was incumbent upon the European Exporters and the EC to substantiate their claims on both the counts. The EC has also claimed that continuation of dumping or no dumping during the period of investigation has no bearing on the injury examination, which is a stand alone investigation to be examined on the basis of the current status of the industry.
21. Section 9A (5) read with Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall from time to time review the need for continued imposition of anti dumping duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal.
22. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.
23. The domestic industry has argued that the review should not have been initiated in the absence of complete evidence substantiating the claims of no dumping by the applicant exporter and no injury to the domestic industry and the burden of proof to substantiate the claim of no dumping solely lies with the applicant at the first instance before it shifts to the defending domestic industry to provide evidence of injury. They have further argued that as per the law, dumping and injury examinations are inseparable in a review and both have to be examined simultaneously to determine whether there is a likelihood of dumping and injury recurring in the event of removal or variation of the duty.
24. The applicants for the review have argued that dumping and injury determinations are not interdependent and even in the presence of dumping the duty needs to be revoked if the Authority determines that the domestic industry suffers no material injury. Therefore, the obligation of the applicant to provide the information on dumping is immaterial to the injury investigation, which has to primarily focus on the material injury.
25. The Authority has examined these arguments and is of the view that the condition 'satisfaction' in Rule 23 refers to the satisfaction of the Authority of the need of continued imposition of duty after conducting a proper investigation and not for initiation of the review. What is required for initiating a review is positive information with the Authority on which the Authority can rely upon to decide

whether a review is required to examine the need for continued imposition of the duty. In the instant case the applicant had filed positive information before the Authority in its review application and the review was initiated based on these positive information filed. Production of evidence to substantiate the claims and counter claims by various parties are the matter of investigation and are to be submitted by the parties including the party making a request for review during the course of investigation. The outcome of the review will however, depend upon the quality of evidence submitted by various parties to the review. Therefore, the Authority is of the view that the review has been correctly initiated on the basis of positive information available with the Authority, which suggested that a review of the duty in force was warranted.

26. However, on the issue of separation of the dumping and injury investigation and the onus of proof to substantiate the claim of no dumping is concerned, the arguments of the applicant have been examined with reference to the Article 11.2, Article 11.3 and Article 3.4 of the Agreement. Article 11.3 provides that as a result of a review the definitive duty can be extended for a period of another 5 years term if such review covers both dumping and injury. This by implication provides for partial review covering either dumping or injury, or a comprehensive review covering both. However, the question arises whether a review covering only injury can completely overlook the degree and extent of dumping.

27. Turning to Article 3 of the Agreement it appears that the parameters of injury to the domestic industry are to be examined with reference to the **dumped imports**. Article 3.1 provides that

*"A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the **volume of the dumped imports** and the effect of the **dumped imports** on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products".*

Further Article 3.4 provides that *"the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the **magnitude of the margin of dumping**;"*

28. Therefore, it appears from the above express provisions of the Agreement that any examination of the condition of the domestic industry in the context of an antidumping investigation has to take into account the underlying effects of the dumping and the magnitude of dumping both in terms of volume and margins.

29. Again turning to Article 11.2 it appears that even if the express provisions of Article 11.2 are broken into two separate parts as has been interpreted by the EC, the second sentence of the proviso provides that the party can ask for a review and Authorities would examine "whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied". This proviso requires the Authority to examine

current injury if any and whether injury can recur if duties are removed. While considering the second part of the proviso the extent of dumping would be a very vital element to determine whether the domestic industry will be injured if the duties are removed even if it does not suffer any injury due the duty protection available.

30. All the above provisions of the Agreement imply that even if a partial review is required to be carried out to examine the condition of the domestic industry in order to decide whether the duty is required to be continued, by implication dumping examination becomes an integral part of the examination and in addition to the current status of dumping and current health of the domestic industry the review has to look to the future to see whether a likelihood of recurrence exists. Therefore, the contention of the EC that injury investigation under a changed circumstances review is a stand alone investigation and can be conducted irrespective of whether dumping continues or not, does not appear to be correct and tenable.

31. The EC has also made another contention that the dumping aspect could very well be withdrawn from their review request and this would not prejudice in any way the legal compliance of the EC's review request. In this connection it may be noted that once a review is initiated based on the positive information submitted by the interested parties, it is the responsibility of the contesting parties to put forward their respective claims and counter claims on various aspects, including dumping and injury. Since the applicants for the review have decided to withdraw the claim of no-dumping and the domestic industry produces evidence of dumping by the EU producers, which is not contested by the EC, the Authority has no option but to draw adverse inference under the best facts clause in terms of article 6.8 of ADA and accept the claim of the defendant as far as dumping is concerned. Assuming that dumping is continuing, based on the adverse facts available, the Authority proceeds to examine the injury to the domestic industry if any, on account of this dumped imports.

32. The Authority notes that neither the exporter nor the European Commission has filed any comments or opposed the above views of the Authority as disclosed in the general disclosure statements.

E. DUMPING DETERMINATION

E. DUMPING DETERMINATION: Normal Value, Export Price and Dumping Margin

E.1 The European Union

Normal Value

33. M/s BASF AG, Germany filed a brief response after initiation of the review with summarized data in respect of their domestic selling prices and export price to India and claimed that against their domestic selling price of ***** EUR/kg at ex-factory level the export price to India is **** EUR/kg at ex-factory level. However, they have not provided the transaction-wise data of their domestic as well as export sales and data on various elements of adjustments claimed. The applicant has also

produced only the summary of their cost structures without any backup data and allocation methodologies. On the basis of these summary data the applicant for the review has claimed that their cost of production is **** EUR/kg. Though the applicant submitted the summary data and requested the Authority to conduct verification if so required, they failed to submit detailed data on any aspect of cost of production, domestic as well as export sales prices in spite of the request to do so and to submit themselves for verification of the data by the Authority. The applicant exporter did not respond to the communication seeking detailed information and consent for verification.

34. In its submission the European Commission has argued that its claim of no dumping should be treated as withdrawn and the Authority need to examine the injury aspect only irrespective of whether dumping is continuing or not. In the preceding section it has been demonstrated that even in a partial review of continuation and likelihood of injury to the domestic industry in the event of withdrawal of duty, assessment of extent of dumping is a vital component of the determination.

35. The domestic industry has argued that M/s BASF is not cooperating in these proceedings as required by law. They have only provided limited submissions on injury and causal link and conveniently chosen not to provide any information pertaining to their normal value. This is contrary to the law and settled jurisprudence. Therefore, in the absence of any other information, the information sourced by the Domestic Industry should be served as the basis of normal value for the purpose of assessment of extent of current dumping. The Domestic Industry has submitted that it made best efforts to procure evidence of the domestic prices prevailing in the E.U. While it has not been able to procure prices for the period of investigation, it has procured an invoice. They have worked out the ex-works price in the EU based on this invoice price for the purpose of estimation of ex-works normal value for the EU exporters.

36. Article 6.8 of the Agreement provide that In cases in which any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. Annex II to the Agreement further provides that such determination can even be made on the basis of information provided by the domestic industry.

37. Therefore, the Authority has adopted the Normal Value for the EU exporters as per the information provided by the domestic industry, in terms of Article 6.8 of the Agreement, which works out to Rs***** per Kg.

Export Price:

38. Export price has been determined on the basis of the DGCI&S data. DGCI&S has reported the following imports of the subject goods during the POI.

	Qty in Kg		
	Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/g EQ		
Countries	2003-04		
	Quantity	Value CIF	Rate Rs/Kg
Total EU	300.59	1071549	3564.84
Singapore	88.24	299033	3389.04
Others	2746.29	9124310	3322.41
Total	3046.88	10195859	3346.33

On the basis of this data the net ex-works export price for the EU exporters has been worked out after allowing various adjustments to the CIF price as per the information provided by the domestic industry. Ex-works export price has been determines as Rs***** per Kg.

Dumping Margin:

39. The normal value determined at the ex-factory level has been compared with the net export price determined at the ex-factory level to determine the dumping margin. The dumping margin for the exports made by the EU exporters has been worked out as:

Dumping Margin Calculations

	Normal Value Rs/Kg *****	Export Price Rs Per Kg *****	Dumping Margin Rs/Kg *****	Dumping Margin %
EU exporters				16.52%

40. The Authority notes that neither the exporter nor the European Commission has commented upon or opposed the methodology or determination of the dumping margin as above and communicated through the general disclosure statements.

E.2 Singapore and Georgia

41. It is noted that there is no export of the subject goods from Georgia and no information about any manufacturer or exporter of the subject goods in this country has been brought before the Authority by any interested party. Therefore, there is no evidence of either dumping or likelihood of dumping from this country.

42. As far as Singapore is concerned, BASF South East Asia Pte. Ltd has submitted that it is not involved in any type of manufacturing activity. It has also been clarified by them that they only carry out coordination and invoicing services for BASF, Germany and the product under consideration is directly shipped to India from BASF Germany. Therefore, it appears that the exports from Singapore can at best be re-exports or mere transshipments of goods originating in Germany. Accordingly, the Normal Value for Singapore has been determined in terms of Article 2.5 of the Agreement. Thus the Normal value in Singapore has been determined as Rs*****per Kg. The net ex-factory export price based on DGCI&S data works out to Rs*****Per Kg.

Dumping Margin (Singapore)

Dumping Margin Calculations

	Normal Value Rs/Kg *****	Export Price Rs Per Kg *****	Dumping Margin Rs/Kg *****	Dumping Margin % 23.69%
Singapore exporters				

43. The Dumping Margin determined for the subject countries have been found to be significant. The Authority notes that none of the interested parties have opposed this determination communicated through the disclosure statements.

F. INJURY DETERMINATION

F.1 Cumulative Assessment of Injury

44. The Authority notes that there is no dumped import from Georgia during the period for which injury is being examined. Though there are imports from Singapore, the same appears to be originating in Germany. Imports from the EU and Singapore have been treated as dumped imports because of the positive dumping margin determined. In view of the condition of competition prevailing and keeping in view of the fact that the imports from EU and Singapore have the same origin, all imports from these countries/ territories have been cumulated for the purpose of injury analysis.

F.2 Continuation of Injury

F.2.1 Views of the Applicants

45. The applicants for the review have submitted that the domestic industry has improved its performance and does not suffer any material injury. They have inter alia submitted that the domestic industry which is represented by sole producer M/s Nicholas Piramal India Ltd. has improved its performance in terms of increase in production and capacity utilization, inventory level and export performance and their export of *****/kg during April to August 2004 at an average price of Rs*****/kg (US\$*****/kg) indicates that no injury exists to the domestic industry. They have further argued that since the imposition of the definitive Anti-dumping duty on Vitamin A Palmitate in January 2003 the DPCO price of Vitamin A Palmitate has been revised downward twice by National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA). Effective 03.03.04 the DPCO price has been reduced from Rs.5402.6/kg (US\$115/kg) to Rs.4141.20/kg (US\$86.38/kg) for Vitamin A Palmitate 1.7. During the same period the prices from EU have increased during current POI (01.04.03 to 31.03.04) as compared to the original POI (01.01.01 to 20.09.01). As a result the minimum import price is currently substantially higher than the price fixed under DPCO (already at non-injurious level). Therefore there is no likelihood of re-occurrence of injury to the domestic industry on export from BASF AG.. They further argue that the profitability of Nicholas Piramal India Ltd. has improved during 2002-

2003 and 2003-2004. Therefore, there is no basis to allege that injury has been caused due to the imports from BASF and therefore there is absence of causal link

F.2.2 Views of the Domestic Industry

46. The domestic industry has submitted that too much reliance has been placed on the price revision undertaken by DPCO (Drug Price Control Order) price in India since the imposition of Antidumping Duty in this matter against which the Domestic Industry has petitioned the concerned authorities for review of the price fixation. They have further submitted that the exercise undertaken by the Hon'ble Designated Authority needs to be separate and distinct from that the DPCO, as they are separate bodies with different consideration and applicable rules.

47. Quoting the final findings in the very same matter the domestic industry has argued that in the said findings itself the Authority had recognized the separation of the prices fixed under DPCO by NPPA and the non-injurious price as ascertained by the authority indicating thereby that there were two separate and distinct prices were fixed by DPCO and the other by the Designated Authority.

48. They have further argued that the above position is sound as it would be unrealistic for the Designated Authority to review its findings each and every time the DPCO revise the price either upwards or downwards.

49. Referring to the arguments of the applicant exporter that the export price of the Domestic Industry is indicative of no injury since the prices are lower than that set by the DPCO, the domestic industry has argued that export price of the Domestic Industry bear no connection with whether or not the exporter is dumping and such dumped imports are causing injury to the Domestic Industry.

50 It has also been argued that the standard for review of injury is beyond the standard required for a finding of injury per se as has been settled in several judicial pronouncements. Which the Appellate Authority has held that while considering the determination of injury, the standard of threat of material injury must necessarily be considered. The domestic industry has argued that given the export prices from E.U. and the capacity available with the exporter and in the EU, there exists a very real and imminent threat of material injury, in addition to the actual injury within the factual matrix of this review.

51 They further argue that within the factual matrix of the case at hand in the original Petition, the average export price from the EU during the period of investigation was Rs.3164.29 per kg. During the period of investigation in this mid-term review, the export price has gone up only marginally in spite of the duty being in force. Therefore, clearly, the price effect is still being felt in the domestic Indian market, whereby the export price has remained virtually unchanged and as a consequence of the reduction of the Customs duty since the original Period of Investigation, the price effect on the Domestic Industry is even worse. Therefore, removal of the Antidumping Duty will enhance the injury to the Domestic Industry.

F.2.3 Examination by the Authority

52. Rule 11 and Annexure II of the Rules requires the Designated Authority to objectively examine:

- a) Both, the volume of dumped imports and the effect of dumped imports in the domestic market for like article and
- b) The consequent impact of these imports on the domestic producers of such products.

Since the imports from the subject countries have been treated as dumped imports, the Authority proposes to examine the volume and price effect of these dumped imports on the domestic industry and also analyse the injury parameters to determine whether the domestic industry is continuing to suffer material injury on account of such dumped imports.

A) Volume effect:

a) Volume of Imports and Import Prices:

53. DGCI&S data for the injury analysis period shows that Imports have taken place from several sources including the European and Singapore during the injury investigation period. However, no imports have been reported from Georgia. It has also been noticed that imports of Vitamin-A Palmitate has been reported under different strength i.e. 1.0 and 1.7 MIU/g. Since both the strengths have been covered under the product under consideration for the purpose of this analysis all imports have been converted into equivalent of Vitamin-A Palmitate 1.7 MIU/g. Accordingly, the import as reported by DGCI&S are as follows:

Import Statement				Vitamin A palmitate 1.7 MIU/g Equivalent					
				Value in Rs CIF)			Qty in Kg		
Year	2001-02			2002-03			2003-04		
Countries	Quantity	Value	Rate	Quantity	Value	Rate	Quantity	Value	Rate
Total EU	7271	22295955	3066.42	1549	4981655	3216.05	300.59	1071549	3564.84
Singapore	350	1104224	3154.93	0	0		88.24	299033	3389.04
Others	2042	5027265	2461.93	1925	6190387	3215.79	2746.29	9124310	3322.41
Total	9663	28427444	2941.89	3474	11172042	3215.90	3135.12	10494892	3347.53

Source DGCI&S

54. The above data shows that total volume of imports has declined compared to the base year after showing a positive growth only during 2001-02. However, share of the subject countries in the total imports have substantially reduced over the years as can be seen from the above table. Though total imports of the subject goods have shown a substantial decline since 2001-02 and drop in import from the subject countries are more significant. However, the prices have moved in a very narrow band during the said period in spite of the fact that the duty on the subject countries is in terms of reference price based on the landed price in India.

55. In its post disclosure submissions the domestic industry has disputed the import data relied upon by the Authority based on the DGCI&S data on the grounds that the data available through the secondary source i.e. IBIS shows higher imports than that reported by DGCI&S. In this connection the Authority notes that the instant investigation covers only Vitamin-A Palmitate. Therefore, while analyzing the import data for dumping margin and injury determination Vitamin A imported in other forms and other unrelated imports reported under the same head have been removed from the analysis to arrive at an accurate analysis. The methodology of analysis of this data has also been explained in the disclosure itself and therefore, the objection of the domestic industry in this regard is not valid.

b) CAPACITY, OUTPUT AND CAPACITY UTILIZATION OF DOMESTIC INDUSTRY

56. The performance of the domestic industry has also been examined with reference to its capacity, output and capacity utilization and impact of the dumped imports on these parameters, if any.

57. The domestic industry has indicated that their total installed capacity for the liquid plant, where the subject goods is manufactured, is 110 MT per annum, on single shift basis. However, it is noted that this installed capacity is not dedicated for the product under consideration and in this plant the company manufacture about 35 different products. Production of individual product varies from year to year depending upon the demand.

58. Therefore, the capacity of the producer has been assessed based on three shift operation for which the plant is actually available and based on total output from the plant of various products, including the product under consideration. Accordingly, the capacity and capacity utilization has been worked out as follows:

Year	Installed capacity (KG)	Production (All Products) (Kg)	Capacity Utilization (%)
2000-01	*****	*****	46.60
2001-02	*****	*****	33.40
2002-03	*****	*****	48.50
2003-04	*****	*****	55.40

59. The above examination shows that the capacity utilization during the period of investigation is the highest in the last four years including the period of investigation. Therefore, capacity or capacity utilization do not appear to indicate any deterioration of the performance of the domestic industry.

c) DEMAND AND MARKET SHARES

60. The total demand has been estimated based on the combined volume of supplies made by the Domestic Industry in the domestic market, captive consumption, imports from other third countries, as well as imports made into the domestic market from the Subject countries.

Quantities in Kgs				
Production of DI	*****	*****	*****	*****
Vitamin A 1.0	*****	*****	*****	*****
Vitamin A 1.7	*****	*****	*****	*****
Total	*****	*****	*****	*****
Total Production 1.7 MIU/g EQ	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	55.31	76.55	97.70
Total Imports 1.7 MIU/g EQ	5100.00	9663.00	3474.00	3135.12
Subject Countries Imports	4550.00	7621.00	1549.00	388.82
% (subject countries)	89%	79%	45%	12%
Domestic sales	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	25.14	67.63	67.40
Captive Consumption	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	291.5	165.3	344.4
Demand	*****	*****	*****	*****
Indexed	100	78.15	78.42	96.68
Market Share				
Domestic Industry	85.53%	64.93%	87.43%	90.80%
Subject countries	12.91%	27.66%	5.60%	1.14%
Others	1.56%	7.41%	6.96%	8.06%

61. As can be seen from the table above, the demand of the subject goods in the Domestic Market decreased marginally from about 35 MT in the year 2000-2001 to 34 MT in the year 2003-2004. At the same time total imports have also shown substantial decline both in absolute term as well as in terms of the market share. The market share of the domestic industry has increased from about 85% to 91% during the corresponding period. As far as the share of dumped imports is concerned, the share of the countries attracting duty in this case, account for only about 1% of the total market share, down from about 13% in the year 2000-01. The share of imports from subject countries as a percentage of total imports as well as total demand shows substantial decline. Therefore, the data indicates that after imposition of duty the condition of the domestic industry has substantially improved in terms of its market share and output and there is no volume effect of the dumped imports. However, the current scenario is in the background of the duty already in force.

B) PRICE EFFECTS:

a) Sales realization of the domestic industry

62 The selling price of the domestic industry has reduced from Rs. *****/Kg in 2000-2001 to Rs. *****/ Kg during the Period of Investigation signifying a reduction of 18.29 % from 2000-2001 levels. There is also a significant reduction in the cost of production during previous three years. The cost of production and net selling prices of the domestic industry as per the record maintained by it has been as follows:

Year	Cost to make & sell Per MT (Rs.)	Selling Price / MT (Rs.)	Indexed data
			Profit / (Loss) per MT (Rs.)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	102.33	93.11	(188.32)
2002-2003	85.15	97.22	466
2003-2004	79.56	81.71	147.40

63. It is noticed that there is a very significant reduction in the cost of production of about Rs*****per Kg in 2000-01 to Rs***** per Kg in 2003-04, a reduction of about Rs***** per Kg. The corresponding decline in selling prices is also about Rs***** per Kg. However, the drop in selling price is significant when compared to the previous year while cost has been reduced marginally.. The profit per Kg of the product after showing significant improvement after imposition of the duty has shown a sharp decline between 2002-03 and 2003-04. However, the drop in selling price seems to have been triggered by the DPCO price revision.

64. It is also noted that the Authority is proposing to fix the Non-Injurious Price for the Period of Investigation as Rs*****/- Per Kg taking into account various factors of production and a reasonable return on the investment. Compared with the above figures the profit margin per Kg of the product would show significant improvement as the selling price of the domestic industry is above the non-injurious price determined by the Authority.

b) PRICE UNDERCUTTING AND UNDERSELLING

65. For the purpose of price undercutting the selling price of the Domestic Industry was compared with the landed value of the subject goods (CIF price + basic customs duty) as per the DGCI&S data for the cumulated imports from the EU and Singapore. Based on the weighted average CIF price of imports from Singapore and the EU the landed price has been worked out as Rs *****Per Kg. The following tables show the extent of price undercutting from EU:

Year	Domestic Selling Price	Import Price (Landed Value)	Price Undercutting
2003-2004	*****	*****	Negative

66. Therefore, the imports from the subject countries have no undercutting effect on the domestic selling prices. Since the landed value of the imports as determined above is also above the NIP determined by the Authority for the domestic industry, the imports also do not have any underselling effect on the domestic prices. The Authority also notes that the NPPA has revised the ceiling price for the product under consideration under the DPCO regulation to the level of Rs.2436/kg on 1.0 MIU/g basis, which works out to Rs.4141.20/kg on 1.7 MIU/g basis with effect from 03.03.20004. Based on the above ceiling price the landed value of imports also work out to have negative price undercutting and underselling effects on the domestic prices.

C) OTHER INJURY PARAMETERS:

67. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed here as follows:

a) PROFITABILITY

68. The profitability of the domestic industry has been analysed from the record of the company:

Indexed	
Year	Profit /(Loss) Rs. Lakhs
2000-2001	100
2001-2002	(49.85)
2002-2003	321.95
2003-2004	114.73

69. It can be seen from the above table that the profits of the Domestic Industry have reduced to Rs. ***** Million during the Period of Investigation from Rs. ***** Million in the previous year 2002-2003. In percentage terms on a yearly basis, the profits during the period of investigation decreased by *****% over the previous year. However, the deterioration of the profit as mentioned above is in spite of the fact that there is a very marginal import of the subject goods from the subject countries and there is no price undercutting or underselling effects of the dumped imports. The landed value of the dumped imports is significantly above the selling price of the domestic industry as well as the DPCO prices. Therefore, the dumped imports do not appear to have contributed to the drop in profitability of the domestic industry.

b) EMPLOYMENT

70. As far as Employment and wages are concerned there is no significant drop in employment level as indicator of injury to the domestic industry. However, the Company seems to have undertaken significant cost cutting measure in terms of wage reduction.

c) PRODUCTIVITY

71. There is a significant drop in productivity in terms of production per employee due to drop in output during this period.

Indexed			
Year	No. of Employees	Production (Kg)	Productivity Per Employee (Kg)
2000-2001	100	100	100
2001-2002	101	52.95	52.19
2002-2003	101	71.69	70.66

2003-2004 (Period of Investigation)	100	91.64	91.65
-------------------------------------	-----	-------	-------

d) INVENTORIES

Year	Opening Stock MT	Indexed	
		Closing Stock MT	
2000-2001	100	100	
2001-2002	50	0	
2002-2003	0	139	
2003-2004	695	21	

72. Inventory position of the Company shows significant improvement. The stocks of the Domestic Industry decreased to *****MT during the Period of Investigation as compared to the opening stock during the same period.

e) Investment and return on investment

73. There has been no capacity addition or any fresh investment by the applicants during the investigation period.

74. The return on investment, after a massive increase after imposition of the duties has come down substantially to about *****%. However, as stated above the drop in profit is not due to the dumped imports which are entering the market at higher landed cost than the non-injurious price as well as the NIP proposed to be fixed by the Authority.

Year	Indexed	
	(%)	
2000-2001	100	
2001-2002	(227)	
2002-2003	692	
2003-2004	211	

f) Magnitude of Dumping

75. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries for the POI, is substantial, even when the antidumping duty is in force.

g) Factors affecting prices

76. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. There is no viable substitute to this product and M/s Nicolas Piramal is the sole producer of the subject good in India. Therefore, domestic competition does not affect the prices. The only other factor that might have affected the prices of the domestic industry is the DPCO prices.

F.3 Other known factors

i) Volume and prices of imports from other sources

77. During the POI, other than the subject countries, imports have taken place from USA, China and Switzerland only. Total import from these sources is much higher compared to imports from the subject countries. The Authority notes that imports from the un-dumped sources is 87% of the total imports and weighted average import price from these sources is lower than the dumped import prices from the subject countries. Therefore, the imports from the subject countries do not appear to have significant effect on the domestic industry, both in terms of volume and value.

ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

Quantity in Kgs	Indexed			
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Demand	100	78.15	78.42	96.68

78. Total domestic demand of the product under consideration, after declining from 2000-01 till 2002-03 has increased substantially during the POI but still remains below the base year level. The share of domestic industry in the demand has shown substantial increase whereas the share of subject countries has substantially decreased. At the same time, share of imports from other sources has increased from 1.5% to 8% of demand. Therefore, contraction in demand is not a significant factor.

iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

79. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. M/s Nicolas Piramal is the sole producer of the subject goods in the country. However, drug price control restricts the selling price of the product for the domestic producers. Moreover, imports from other sources have fairly sizable presence in the Indian market, which has grown substantially.

iv) Development of technology and export performance

80. Technology or technology related issues have not been raised by any interested party as cause of injury to the domestic industry. However, the export performance of the domestic industry has been raised by the applicants as a cause of injury to the domestic industry, as the domestic producers exports the subject goods to other countries at substantially lower prices. However, the domestic industry has claimed that the export price decision is based on their market entry strategy in order to establish new markets for this product as they are too small a player in the global market. Authority has examined this issue and is of the view that the domestic industry has exported rather a very small quantity only during the POI as a market entry move and that does not substantially affect the profitability of the company.

v) **Productivity of the Domestic Industry**

81. Productivity of the domestic industry in terms of labour output and daily output has shown substantial decline compared to the base year. However, compared to the previous year the productivity has improved substantially.

F.5 Likelihood of recurrence of dumping and injury

82. Since the Authority has already determined that the subject goods are continuing to enter the Indian market at dumped prices from the subject countries, an analysis of recurrence is not required. However, looking at the non-cooperation of the exporters to provide credible evidence on the normal value of the product in the subject countries it can be reasonably concluded that the exports would continue to enter the market at dumped prices. But looking at the price level at which the product is entering the Indian market from all sources it is unlikely that further reduction of the export prices could take place immediately.

83. Therefore, it is pertinent to examine whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed or varied. It has already been established that the landed value of imports from the subject countries without the antidumping duty is significantly above the selling price of the domestic industry and the NIP determined by the Authority for the domestic industry. Therefore, removal of the duty fixed in terms of reference price is not likely to materially affect the price level.

84. However, in addition to the examination of material injury, likelihood of recurrence of injury or threat of injury to the domestic industry has been examined by the Authority on the basis of the claims made by the domestic industry.

85. The Domestic Industry has submitted that the threat of material injury should be examined in terms of Annexure II (vii) of the Rules, which states as under:

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors and;

- (a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- (b) *Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- (c) *Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports and,*

(d) *Inventories of the article being investigated."*

86. Though the above provision do not provide appropriate parameters for examination of likelihood of recurrence of injury in a review investigation, in the absence of any express provision In this regards the Authority has examined some of these parameters to draw inference on the subject.

87. In the instant case, the imports of the subject goods have decreased over the injury period and demand also do not show a very healthy growth to attract more imports. The domestic industry has submitted that as per their market intelligence the capacities of the Exporters worldwide, is estimated to be around 5000 MT and the exporters have sufficient freely disposable capacities. There are only two global producers having plants worldwide, and domestic industry's capacities are too small compared to these global players. Therefore, these producers have tremendous capacity to undercut the prices to establish themselves in the Indian market. However, the current import data does not indicate that a significant price undercutting will occur immediately, if the duty is withdrawn. The cost of production and the selling price of the domestic industry during the period of investigation do not show significant price suppression or depression due to the landed value of dumped imports, which is above these levels.

F.6 Determination of Non-injurious Price of the Domestic Industry

88. Non-injurious Price for the subject goods has been worked out by the Authority after a detailed analysis and scrutiny of information provided by the domestic industry. Weighted average Non-injurious price for the domestic industry is proposed to be fixed by the Authority as Rs. ***** per Kg. The domestic industry in its post disclosure submissions has disputed the non-injurious price fixed by the Authority and has argued that the NIP fixed by the Authority is even below the DPCO price fixed after detailed audit by the competent Authority. The Authority notes that the methodology and elements of NIP has been explained to the domestic industry after the disclosures were issued. Therefore, the NIP fixed is confirmed by the Authority.

F.7 Magnitude of Injury and injury margin

89. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. Since the landed value of the dumped imports has been found to be above the Non-injurious price, injury margin has been found to be negative during the POI.

G. Conclusion:

90. Having examined all the above parameters and various arguments of the interested parties, the Authority concludes that:

- a. Dumping continues from the subject countries and is likely to continue
- b. However, the domestic industry does not suffer any material injury on account of these dumped imports as the import prices and the sales

realizations of the domestic industry are above the non-injurious price so determined.

- c. Injury to the domestic industry is not likely to recur if the duties are revoked.

H. Recommendations

91. Having concluded that the domestic industry suffers no material injury on account of imports of the subject goods from the subject countries, the Authority finds no justification for continuation of the duty against these countries and therefore, in terms of Rule 23 of the said Rules recommends revocation of duty in force against these countries.

I. Further Procedures

92. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority